

RNI NO- UPHIN/2018/76675

वर्ष- 07, अंक-04 मास- अप्रैल 2026

मूल्य-

20/-

निर्माणशाला

अप्रैल 2026

टाइम्स

मासिक हिन्दी पत्रिका



उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस से सजा
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रतीक चिन्ह

कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम

प्रमुख गतिविधियाँ और प्रदान की जाने वाली सेवाएँ



- किसानों और पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक फॉर्मूलेशन का विकास।
- रासायनिक कीटनाशकों के हरित विकल्प के रूप में जैव-वनस्पति कीटनाशक फॉर्मूलेशन का विकास।
- विश्लेषणात्मक वर्णन।
- खाद्य उत्पादों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण।
- परंपरागत और ड्रोन स्प्रे द्वारा कीटनाशकों की बायो एफीकेसी और फाइटोटॉक्सिसिटी अध्ययन।
- विद्यार्थियों, कीटनाशक उद्योगों के तकनीकी व्यक्तियों और शिक्षा जगत के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण।
- देश के विभिन्न स्थानों पर किसानों के समूह के लिए फसल रक्षा पर कार्यशालाएँ।



अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:-

निदेशक, कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)।

रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार

सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुरुग्राम - 122016 हरियाणा

ई-मेल: director@ipft.gov.in, admin.ipft@gov.in फ़ोन नंबर: 0124-2455405

कीटनाशकों के अंतः विषय अनुसंधान, विश्लेषण, निगरानी और प्रभावकारिता के माध्यम से समाधान प्रदान करना

'विद्युत सखी' बनीं
राजश्री, लिख रही ...

07

ईरान-इजरायल-
अमेरिका युद्ध ...

14

छोटे उद्योगों पर दोहरी
मार...

21

दिल्ली का द्वारका ...

34



49

इजरायल-ईरान युद्ध का
साइड इफेक्ट

निर्माणशाला टाइम्स

मूल्य: 20 रुपये, अप्रैल 2026
वर्ष-7 अंक: 04, पृष्ठ: 52

प्रधान संपादक
मनोज कुमार सिंह

संपादक
अहमद हसन

सह संपादक
दिव्यांश मिश्रा

ब्यूरो प्रमुख
उत्तराखंड-
उत्तर प्रदेश-
दिल्ली-
बिहार-
हरियाणा-
झारखंड-

विनय त्रिवाल
लल्लन कुमार मिश्रा
दिनेश कुमार सिंह
मोहम्मद अली
संतोष कुमार सिंह
परवेज कमाल

ले आउट डिजाइनिंग- सुरेन्द्र सिंह

कार्यालय

मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी सैयद नौशाद
मंज़र,
मुद्रित- नीलू प्रिंटिंग प्रेस, E-33, सेक्टर-
7, नोएडा, उत्तर प्रदेश से,
प्रकाशित- टी-1, श्री जी कॉम्प्लेक्स,
सेक्टर-5, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से,
संपादक- अहमद हसन,
पत्र का नाम- निर्माणशाला टाइम्स
(Nirmanshala Times),

RNI NO-
UPHIN/2018/76675

विज्ञापन प्रसार संपर्क और
पत्र व्यवहार
NST Media
Plot No. 116, Udyog
Kendra II, Ecotech III,
Greater Noida - 201306,
Distt. Gautam Buddha
Nagar
(Uttar Pardesh)

Web:
www.nirmanshalatimes.com
E-mail:
nirmanshalatimes@gmail.com
Mob No: +919540284632

निर्माणशाला टाइम्स विज्ञापनकर्ताओं के दावों को सत्यापित नहीं करता।

विश्व भर में सर्वाधिक सुरक्षित, किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबन्धित, सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता।

सभी विवादों का निपटारा, दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली समक्ष अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट – उत्तर भारत के विकास का नया द्वार

सैयद नौशाद मंजर

भारत में बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार के बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) एक महत्वाकांक्षी और दूरगामी परियोजना के रूप में उभर रहा है। नोएडा के समीप जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे उत्तर भारत की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। यह परियोजना लंबे समय से प्रतीक्षित थी, और अब इसके साकार होने से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

जेवर एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल करने की योजना है। इसका निर्माण कई चरणों में किया जा रहा है, जिससे भविष्य की जरूरतों के अनुसार इसका विस्तार संभव होगा। यह एयरपोर्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते हवाई यातायात के दबाव को कम करेगा। वर्तमान में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी क्षमता के करीब काम कर रहा है, ऐसे में जेवर एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरेगा।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह परियोजना लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। निर्माण कार्य से लेकर एयरपोर्ट संचालन, लॉजिस्टिक्स, होटल, पर्यटन और अन्य सहायक सेवाओं में बड़े पैमाने पर नौकरियां उत्पन्न होंगी। इसके साथ ही, आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र को एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

हालांकि, इस परियोजना के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय किसानों के पुनर्वास जैसे मुद्दे समय-समय पर सामने आते रहे हैं। कई किसानों ने मुआवजे और पुनर्वास को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। ऐसे में सरकार और संबंधित एजेंसियों के लिए यह जरूरी है कि वे पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ इन मुद्दों का समाधान करें। विकास और मानवीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी इस परियोजना पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एयरपोर्ट निर्माण से भूमि उपयोग में बदलाव, जैव विविधता पर प्रभाव और प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए, सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी और जल संरक्षण जैसे कदम इस दिशा में सहायक हो सकते हैं।

संपर्क व्यवस्था के लिहाज से जेवर एयरपोर्ट का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख मार्गों से जोड़ा जा रहा है, जिससे यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को सुगमता मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में रियल एस्टेट का विकास भी तेजी से होगा, जिससे निवेशकों और आम लोगों दोनों को लाभ मिलेगा।

सामाजिक दृष्टि से भी यह परियोजना परिवर्तनकारी साबित हो सकती है। बेहतर रोजगार और व्यापारिक अवसरों के कारण लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि, इसके लिए यह जरूरी है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे। अंततः, जेवर एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि इसे सही योजना, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन के साथ विकसित किया जाए, तो यह आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के सहयोग से यह परियोजना एक आदर्श मॉडल बन सकती है, जो विकास और समावेशिता का संतुलित उदाहरण प्रस्तुत करे।



नव निर्माण के 9 वर्ष: यूपी बना पर्यटन का सिरमौर

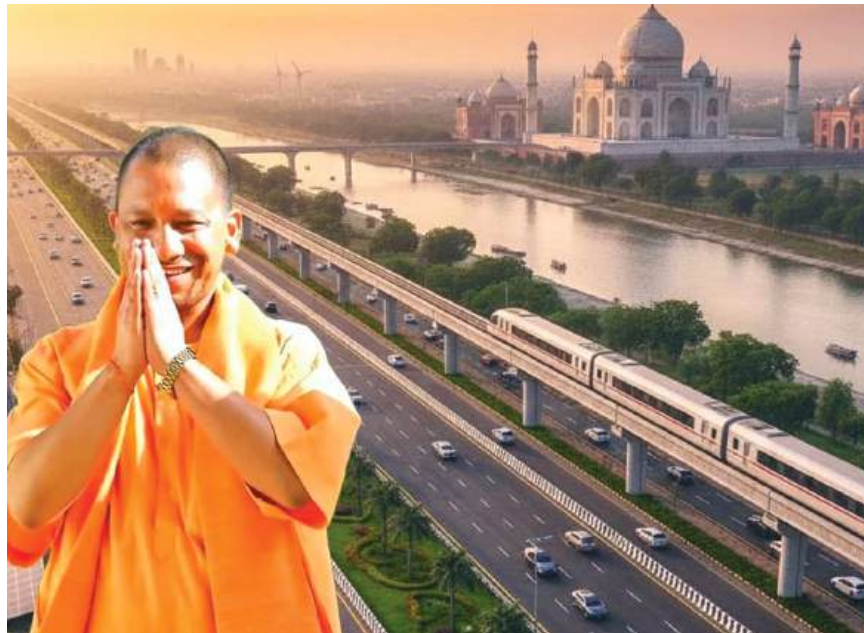
यूपी पर्यटन नीति- 2022 और टेंपल एंड फेस्टिवल इकॉनामी का हुआ सफल क्रियान्वयन, वैश्विक स्परिचुअल टूरिज्म हब के रूप में उभरा यूपी

भारतीय अध्यात्म के केंद्र काशी, अयोध्या, मथुरा में पर्यटन सुविधाओं का विकास, यूपी बन रहा वैश्विक स्परिचुअल टूरिज्म हब

आईआईएम लखनऊ ने अपने अध्ययन में योगी सरकार की टेंपल इकॉनामी की सराहना की

लखनऊ- उत्तर प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में सफलता की जो नई कहानी लिख रहा है, वह केवल पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में आस्था और अर्थव्यवस्था एक-दूसरे की पूरक बनकर प्रदेश में पर्यटन की विकास यात्रा को नई दिशा दे रही है। इस दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप तैयार की गई पर्यटन नीति-2022 के सफल क्रियान्वयन के साथ इको टूरिज्म का विकास, पर्यटन सुविधाओं में अवसंरचनात्मक सुधार, बेहतर कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे और परिवहन सेवाओं के विस्तार ने यूपी में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही योगी सरकार का 'टेंपल एंड फेस्टिवल इकॉनामी' का मॉडल उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक स्परिचुअल टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर रहा है। आईआईएम लखनऊ ने कुछ समय पहले अयोध्या में पर्यटन को लेकर अध्ययन किया था। इसमें उसने योगी सरकार की टेंपल इकॉनामी की सराहना की है।

योगी सरकार के नौ वर्षों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, जिसकी गवाही पर्यटन के आंकड़े देते हैं। योगी सरकार के पहले वर्ष 2017 में यूपी में लगभग 23.75 करोड़ पर्यटक आए थे, वहीं 2019 में यह संख्या लगभग दोगुनी बढ़कर 54.06 करोड़ पहुंच गई। हालांकि, इसमें कोविड महामारी के दौरान गिरावट दर्ज की गई, लेकिन योगी सरकार की पर्यटन नीति - 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन से तेज रिकवरी हुई। परिणाम यह हुआ कि



वर्ष 2024 में 64.91 करोड़ पर्यटकों के साथ यूपी देश में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों वाला राज्य बन गया और विदेशी पर्यटकों के मामले में चौथा। यही नहीं, वर्ष 2025 में महाकुंभ-2025 के आयोजन से पर्यटकों की संख्या अभूतपूर्व रूप से बढ़कर 156.18 करोड़ तक पहुंच गई। गौरतलब है कि पिछले 9 वर्षों में यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग सात गुना बढ़ चुकी है। वर्तमान में राष्ट्रीय पर्यटन में यूपी की हिस्सेदारी 21.9 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो यूपी को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में उल्लेखनीय संकेत है।

प्रदेश में 5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन

मुख्यमंत्री के विजन को साकार करती उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 प्रदेश में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को साकार करने वाली साबित हुई है। इस नीति के तहत होटल, होमस्टे, इको-टूरिज्म, वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म समेत 22 गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत अब तक 36,681 करोड़ के निवेश लक्ष्य को हासिल किया गया है। साथ ही 1,684 से अधिक पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। जिससे

प्रदेश में 5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ और महिलाओं का भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश में 12 से अधिक टूरिस्ट सर्किटों का निर्माण

धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न तीर्थ परिषदों का निर्माण कर उनका कायाकल्प किया गया। जिससे एक ओर तो तीर्थों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में बढ़ोतरी हुई, साथ ही इन क्षेत्रों में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। इसमें अयोध्या, देवीपाटन, ब्रज तीर्थ, विंध्याचल, चित्रकूट, नैमिषारण्य, शुक तीर्थ विकास परिषदों का गठन प्रमुख है। इसके साथ ही प्रदेश में 12 से अधिक टूरिस्ट सर्किटों, रामायण, कृष्ण, बौद्ध, जैन, सूफी, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट आदि का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 83 धार्मिक मार्गों के चौड़ीकरण व विकास से श्रद्धालुओं की यात्रा और सुगम हुई है।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया

प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इसमें लखनऊ



में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना, कौशांबी में संग्रहालय, बाराबंकी में बाबू केडी सिंह संग्रहालय, गोरखा रजिमेंट सेंटर, मेरठ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित संग्रहालय और गोरखपुर में शहीद स्मारक जैसे निर्माण कार्य उल्लेखनीय हैं। प्रयागराज में आजाद पार्क और 'देखो प्रयागराज' ट्रेल का अनुभव, बुंदेलखंड (महोबा) का विरासत पर्यटन स्थल के रूप में विकास, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, कुशीनगर में बुद्ध थीम पार्क, आगरा स्थित बटेश्वर और श्रावस्ती का समेकित पर्यटन विकास जैसी विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश में सांस्कृतिक समृद्धि के साथ पर्यटन विकास की वाहक साबित हो रही हैं।

राज्य में 49 इको-टूरिज्म परियोजनाएं शुरू की गईं। राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगस्त 2022 में यूपी इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। जिसके माध्यम से प्रदेश के प्रमुख इको टूरिज्म केंद्रों दुधवा, कतर्नियाघाट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ और सोहगीबरवा वन क्षेत्रों के साथ अन्य प्राकृतिक पर्यावासों में भी नाइट स्टे, वॉच टॉवर, नेचर ट्रेल, कैफेटेरिया, होमस्टे और बर्ड वॉचिंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। राज्य में 49 इको-टूरिज्म परियोजनाएं शुरू की गई हैं, साथ ही ग्रामीण पर्यटन के लिए 234 गांवों का चयन किया गया है। प्रदेश के सभी

जिलों में युवा पर्यटन क्लबों का गठन कर स्थानीय सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

‘टेंपल एंड फेस्टिवल इकॉनामी’ मॉडल सबसे प्रभावशाली कारक सिद्ध हुआ

यही नहीं, योगी सरकार का ‘टेंपल एंड फेस्टिवल इकॉनामी’ मॉडल यूपी में पर्यटन विकास का सबसे प्रभावशाली कारक सिद्ध हुआ है। इसका सबसे सशक्त उदाहरण अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में देखने को मिला। अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2017 के 2.84 लाख से अविश्वसनीय रूप से बढ़कर वर्ष 2024 में 16.44 करोड़ के पार पहुंच गई। यही नहीं, वर्ष 2025 में भी अयोध्या में 29.95 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। इसी क्रम में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, प्रयागराज में कुंभ और महाकुंभ के आयोजनों ने इन तीर्थक्षेत्रों में पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया है। योगी सरकार का यह मॉडल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वर्ष 2017 से 2025 तक 197 ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों का जीर्णोद्धार हुआ, जिससे प्रदेश में पर्यटनजनित व्यापार और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में त्योहार और उत्सव अब दिव्य-भव्य महोत्सव का रूप ले चुके हैं। इसमें अयोध्या

का दीपोत्सव, वाराणसी की देव दीपावली और मथुरा के ब्रज और बरसाना के होली उत्सव में देशी-विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगती है। यही नहीं, प्रयागराज के महाकुंभ-2025 में आए 66.30 करोड़ पर्यटकों ने सारे विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इनके साथ ही ललितपुर का लखरी मेला, बुलंदशहर का कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला, मेरठ का नौचंदी मेला, आगरा का बटेश्वर पशु मेला, बलिया का ददरी मेला जैसे क्षेत्रीय आयोजनों को भी भव्य रूप दिया गया है। ये आयोजन होटल, रेस्टोरेंट, खुदरा व्यापार, परिवहन, प्रसाद एवं फल-फूल उद्योग और सेवा क्षेत्र को सीधा लाभ पहुंचाते हैं। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनाने की ओर अग्रसर है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका योगी सरकार की पर्यटन विकास नीति- 2022 और ‘टेंपल एंड फेस्टिवल इकॉनामी’ मॉडल की है। यही नहीं, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के मामले में राजस्थान, केरल, तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच चुका है। साथ ही भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के केंद्र काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्पिरिचुअल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करेगी।

‘विद्युत सखी’ बनीं राजश्री, लिख रहीं बदलाव की नई कहानी

स्वयं सहायता समूह की ताकत- राजश्री शुक्ला ने बिजली बिल सेवा से जीता पूरे गांव का विश्वास

लखनऊ- बाराबंकी की राजश्री शुक्ला आज उस बदलाव की मिसाल हैं, जो सरकारी योजनाओं और व्यक्तिगत मेहनत के संगम से संभव हुआ है। कभी सीमित संसाधनों के साथ जीवनयापन करने वाली राजश्री आज विद्युत सखी के रूप में अलग पहचान बना चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरु की गई इस पहल ने उन्हें न सिर्फ रोजगार दिया, बल्कि उन्हें अपने जिले में एक नई पहचान भी दी है। घर-घर जाकर बिजली बिल संग्रह करने का उनका काम आज हजारों लोगों के लिए सुविधा और भरोसे का प्रतीक बन चुका है।



घर-घर सेवा, गांव को मिली सुविधा- डिजिटल भुगतान से बदली ग्रामीण व्यवस्था

राजश्री का काम केवल बिल संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन में एक बड़ी सुविधा लेकर आया है। उनके प्रयासों से गांव के लोगों को लंबी कतारों में खड़े होने से राहत मिली है और समय पर बिल जमा होने से बिजली विभाग के राजस्व संग्रह में भी सुधार हुआ है। अब तक वे 81,000 से अधिक बिजली बिल की राशि एकत्र कर चुकी हैं। उनकी मेहनत का परिणाम है कि उन्होंने अभी तक कुल 18 करोड़ से अधिक की राशि का बिल जमा कराया है। आज उनकी वार्षिक आय 10 लाख से अधिक है, जो यह दर्शाती है कि सही अवसर मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं।

राधा स्वयं सहायता समूह से मिली सफलता- लाख रुपये तक पहुंची आय

राजश्री ‘राधा स्वयं सहायता समूह’ से जुड़ी हैं और उन्होंने वर्ष 2021 में मात्र 30,000 की बैंक सहायता से इस काम की शुरुआत की थी। शुरुआत में यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने गांव-गांव जाकर जागरूकता शिविर लगाए, लोगों को डिजिटल भुगतान, बिल सेवाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में

जानकारी दी। कुछ समय बाद ही उनकी मासिक आय 80 हजार रुपये से अधिक हो चुकी है। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने धीरे-धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। आज स्थिति यह है कि गांव की महिलाएं खुद उन्हें फोन कर बिल भुगतान में सहायता मांगती हैं। यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया है।

सम्मान और प्रेरणा- एक महिला से हजारों तक पहुंचा आत्मनिर्भरता का संदेश

राजश्री शुक्ला को इस उपलब्धि को राज्य स्तर पर भी सराहा गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें सम्मानित किया। उनकी सफलता न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़कर न केवल खुद को, बल्कि समाज को भी सशक्त बना सकती हैं।

9 नवंबर 2024 को आयोजित आकांक्षा हट कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश की 5 मेधावी महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें विद्युत सखी राजश्री शुक्ला भी शामिल थीं। इसके अलावा उन्हें 15 अगस्त 2023 और 26 जनवरी 2024 और 15

अगस्त 2025 के बीच मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

उनकी उपलब्धियों के चलते उन्हें 15 अगस्त 2024 को दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री की ओर से आमंत्रित किया गया, जहां वे ध्वजारोहण समारोह की साक्षी बनीं।

इसके साथ ही 14 अगस्त 2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय में आयोजित बैठक एवं भोज कार्यक्रम में भी उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।

योगी सरकार की पहल ‘विद्युत सखी’ से बदलता उत्तर प्रदेश

आज उत्तर प्रदेश में विद्युत सखियां सक्रिय रूप से अच्छा काम कर रही हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हजारों करोड़ रुपये के बिजली बिल संग्रह कर राज्य की व्यवस्था को मजबूत किया है। यह पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तीकरण, डिजिटल सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास का एक सशक्त मॉडल बन चुकी है। राजश्री शुक्ला जैसी महिलाएं इस बात का प्रमाण हैं कि जब सरकार की योजनाएं सही दिशा में लागू होती हैं और लोग उन्हें अपनाते हैं, तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं, बल्कि स्थायी हो जाता है।

तराई में आई श्वेतक्रांति से 51 हजार महिलाएं बनीं उद्यमी

लखनऊ- उत्तर प्रदेश के तराई और आसपास के क्षेत्र अब महिला सशक्तीकरण और आर्थिक क्रांति का नया केंद्र बन चुके हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आई श्वेतक्रांति ने बरेली, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर और रामपुर जैसे जिलों की दिशा और दशा बदल दी है। यहां 1500 गांवों में फैले दुग्ध व्यवसाय के जरिए 51 हजार महिलाएं उद्यमी बनकर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। इन सभी महिलाओं के खाते में हर महीने 03, 13 और 23 तारीख को पैसा आ जाता है।

सृजनी एमपीसीएल के नेतृत्व में तराई के इन जिलों में अब हर सुबह दूध संग्रहण किया जाता है, जहां महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादन से लेकर संग्रहण और विपणन तक की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। परिणामस्वरूप क्षेत्र में प्रतिदिन एक लाख लीटर से अधिक दूध का कारोबार हो रहा है और अब तक महिलाएं सवा दो सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यवसाय कर चुकी हैं। जो क्षेत्र पहले विकास की दौड़ में पिछड़े माने जाते थे, वहीं योगी सरकार के कार्यकाल में अब महिलाओं की मेहनत से नई आर्थिक पहचान बन रही है और गांव-गांव में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

गांव की अर्थव्यवस्था की प्रमुख संचालक बन रही महिलाएं

इस परिवर्तन के पीछे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने का काम किया। इसी का परिणाम है कि महिलाएं अब केवल सहयोगी नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था

**योगी सरकार के 9 वर्षों में विकास के पहिए ने पकड़ी रफ्तार,
तराई के 1500 गांवों में फैला दूध का कारोबार**

हर महीने 03, 13 और 23 तारीख को आता है सभी के खाते में पैसा

**एक लाख लीटर से ज्यादा प्रतिदिन की बिक्री से महिलाओं ने
किया सवा दो सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार**

की प्रमुख संचालक बन गई हैं।

**छह हजार से अधिक गांवों में
सक्सेज मॉडल**

प्रदेश स्तर पर भी यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश आज दुग्ध उत्पादन में देश में अग्रणी बन चुका है, जहां ग्रामीण महिलाएं प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रही हैं। 31 जिलों में

महिलाओं ने पांच हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया है और छह हजार से अधिक गांवों में इस मॉडल ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है।

तराई की यह श्वेतक्रांति केवल आर्थिक उन्नति की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी सशक्त उदाहरण है। महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही हैं।



सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की बड़ी छलांग, 2025-26 में रिकॉर्ड 3.47 लाख संयंत्र स्थापित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए रिकॉर्ड 3,47,729 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए हैं। इस दौरान राज्य की कुल स्थापित क्षमता 1161.756 मेगावाट तक पहुंच गई, जो प्रदेश की ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेजी को दर्शाता है।

माहवार आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष की शुरुआत अप्रैल 2025 में 15,836 इंस्टॉलेशन से हुए थे, जो मई और जून में बढ़कर क्रमशः 18,509 और

18,494 तक पहुंच गए। जुलाई से इस रफ्तार में बड़ी उछाल देखने को मिली, जहां 29,850 संयंत्र स्थापित हुए और क्षमता 100 मेगावाट के पार पहुंच गई। अगस्त और सितंबर में भी यह गति बरकरार रही, जबकि अक्टूबर में थोड़ी गिरावट के बाद नवंबर और दिसंबर में फिर से तेजी आई। नवंबर में 30,894 और दिसंबर में 31,164 इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए।

वास्तविक तेजी वर्ष के अंतिम तीन महीनों में देखने को मिली। जनवरी 2026 में 33,314, फरवरी में 35,804 और मार्च में रिकॉर्ड 52,729 संयंत्र स्थापित किए गए, जो पूरे वर्ष का सर्वाधिक आंकड़ा रहा। केवल मार्च माह में ही 173.84 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई, जो किसी एक माह में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है।

यूपीनेडा के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि

अंतिम तिमाही में आई यह तेजी सरकार की प्रभावी नीतियों, सब्सिडी योजनाओं और जमीनी स्तर पर मजबूत क्रियान्वयन का परिणाम है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती और स्वच्छ बिजली भी उपलब्ध हो रही है।

इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश देश में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में तेजी से उभर रहा है। उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में नंबर वन राज्य बन गया है।

कुल मिलकर उत्तर प्रदेश में कुल 4,48,233 सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिससे रोजाना 1524 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। लगातार बढ़ती इंस्टॉलेशन दर यह संकेत देती है कि आने वाले समय में प्रदेश ग्रीन एनर्जी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और तेजी से हासिल करेगा।





यूपी की अर्थव्यवस्था का गेमचेंजर होगा जेवर एयरपोर्ट, कृषि से उद्योग तक दिखेगा व्यापक असर

7 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता और लगभग 10 लाख टन कार्गो हैंडलिंग के साथ कृषि, एमएसएमई और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मिलेगी नई गति

लखनऊ/नोएडा- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने जा रहा है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके शुभारंभ के साथ ही यह मेगा प्रोजेक्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत स्ट्रेटिजिक इंजन के रूप में सामने आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप विकसित यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लंबे समय से लैंड-लॉकड आर्थिक पोटेंशियल को अनलॉक करेगा और कृषि, एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन व उद्योगों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के चलते यह परियोजना न केवल प्रदेश की जीडीपी को नई गति देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं,

वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर एक मजबूत पहचान भी दिलाएगी।

किसानों की आय में 20-30% तक वृद्धि की संभावना

पूर्व सीएफओ, एयर इंडिया सैट्स और यूपीडीएफ के चेयरमैन सीए पंकज जायसवाल के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा यह प्रोजेक्ट 7 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता और लगभग 10 लाख टन कार्गो हैंडलिंग के साथ कृषि, एमएसएमई और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति देगा। इसके जरिए फल, सब्जी, डेयरी और सजावटी फूल जैसे पेरिशेबल उत्पाद सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे, जिससे फार्म-टू-ग्लोबल मार्केट मॉडल मजबूत होगा और किसानों की आय में 20-30% तक वृद्धि की संभावना

है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स लागत घटने, निर्यात बढ़ने और वैश्विक कनेक्टिविटी बेहतर होने से उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मानचित्र पर एक सशक्त पहचान मिलेगी।

जीडीपी में 1% की वृद्धि संभव

उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में व्यापार और पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। यह एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों को एक वैश्विक पर्यटन सर्किट से जोड़ेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते धार्मिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस ट्रेवल को भी नई गति मिलेगी। जब यह एयरपोर्ट अपने पूर्ण क्षमता के साथ

संचालित होगा, तो इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभव है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।

रोजगार सृजन का बनेगा बड़ा केंद्र

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का प्रमुख इंजन बनने जा रहा है। पंकज जायसवाल के अनुसार, शुरुआती 5 वर्षों में एयरपोर्ट ऑपरेशन, ग्रांड हैंडलिंग, सिविलीटी, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में 20,000 से अधिक तथा एमआरओ, कार्गो, लॉजिस्टिक्स और एविएशन सर्विसेज में 30,000 से अधिक, कुल मिलाकर 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। वहीं कृषि, ट्रांसपोर्ट, सप्लाय चैन, एमएसएमई, होटल और पर्यटन जैसे सेक्टरों में 5 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो लंबी अवधि में 40-50 लाख तक पहुंच सकते हैं। प्रदेश में मौजूद लगभग एक करोड़ एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जोड़कर यह एयरपोर्ट न केवल रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी व्यापक स्तर पर गति देगा।

रियल एस्टेट और इंडस्ट्री को मिलेगा व्यापक बूस्ट

जेवर एयरपोर्ट के विकास के साथ उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट और औद्योगिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) तेजी से एक प्रीमियम निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेंगे, वहीं बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन तक अर्बन एक्सपेंशन कॉरिडोर विकसित होकर नए शहरों और टाउनशिप को जन्म देगा। एयरपोर्ट के आसपास होटल, वेयरहाउस, ऑफिस स्पेस, लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा सेंटर में बड़े निवेश आकर्षित होंगे, जिससे रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैनुफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे निर्यात-उन्मुख उद्योगों को नई गति मिलेगी, जो इस

क्षेत्र को एक मजबूत इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करेगा।

इंडस्ट्रियल सेक्टर को नई रफ्तार



एयरपोर्ट के संचालन से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को उल्लेखनीय गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी और कम लॉजिस्टिक्स लागत के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैनुफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे प्रमुख सेक्टर तेजी से विकसित होंगे। खासकर निर्यात उन्मुख उद्योगों को वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे उत्पादन और निवेश दोनों में वृद्धि होगी। यह एयरपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत सप्लाय चैन नेटवर्क तैयार करेगा, जो उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख मैनुफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका

वैश्विक एविएशन हब बनने की क्षमता

जेवर एयरपोर्ट को केवल दिल्ली-एनसीआर के सहायक एयरपोर्ट के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के एक बड़े मल्टी-मोडल इंटरनेशनल एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

यह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करते हुए एयर ट्रैफिक को संतुलित करेगा। 5 रनवे की प्रस्तावित क्षमता के साथ यह देश का सबसे

बड़ा एविएशन हब बनने की दिशा में अग्रसर है। इसकी रणनीतिक स्थिति इसे एशिया और यूरोप के बीच एक अहम ट्रांजिट केंद्र बना सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में बड़ा विस्तार होगा। साथ ही, बदलते वैश्विक हालात के बीच यह दुबई, दोहा और अबु धाबी जैसे स्थापित हब के विकल्प के रूप में उभरकर भारत की एविएशन क्षमता को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखता है।

एमएसएमई और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मिलेगा मेगा बूस्ट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रणनीतिक लोकेशन इसे एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर के लिए गेमचेंजर बनाती है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के करीब होने के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख हाईवे से इसकी मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी इस क्षेत्र को देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बना सकती है। इसके परिणामस्वरूप वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर में तेजी से विस्तार होगा, जिससे सप्लाय चैन अधिक कुशल बनेगी। साथ ही, भारत में 13-14 लाख तक रहने वाली लॉजिस्टिक लागत में कमी आने से एमएसएमई सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और निर्यात को नई गति मिलेगी।

निवेश और विदेशी कंपनियों के लिए बढ़ेगा आकर्षण

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकसित हो रही एयरोसिटी, लॉजिस्टिक्स पार्क और इंडस्ट्रियल क्लस्टर उत्तर प्रदेश को निवेश का नया केंद्र बना रहे हैं। राज्य सरकार की एफडीआई-फ्रेंडली नीतियों और बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माहौल के चलते घरेलू और विदेशी निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ेगा। बेहतर कनेक्टिविटी और कम होती लॉजिस्टिक्स लागत के कारण उत्पादन लागत में कमी आएगी, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

साथ ही चीन+1 स्ट्रेटजी के तहत वैश्विक कंपनियों के लिए यह क्षेत्र एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरेगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डिफेंस मैनुफैक्चरिंग जैसे उभरते सेक्टरों में बड़े निवेश की संभावनाएं हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा देश का बड़ा एमआरओ हब

पीएम मोदी ने एमआरओ सुविधा का किया
शिलान्यास, विमान रखरखाव में
आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम

अभी मेंटेनेंस के लिए 85% विमान मेजने
पड़ते हैं विदेश, जेवर में एमआरओ हब से
रोजगार, निवेश व तकनीकी कौशल को भी
मिलेगा बूस्ट

जेवर- उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के एविएशन सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। यहां अत्याधुनिक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) हब विकसित किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश को विमान रखरखाव के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

एमआरओ में आत्मनिर्भरता जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर बताया कि भारत अभी विमान रखरखाव के मामले में काफी हद तक विदेश पर निर्भर है। देश के लगभग 85% विमान अभी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए विदेश भेजे जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। उन्होंने इस स्थिति को बदलने पर जोर देते हुए कहा कि भारत को एमआरओ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना समय की आवश्यकता है और इसके लिए देशभर में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

अकासा एयर के साथ रणनीतिक साझेदारी

नोएडा एयरपोर्ट परिसर में अकासा एयर के सहयोग से पहली एमआरओ सुविधा स्थापित की जाएगी। यह अत्याधुनिक केंद्र विमान रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी सेवाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार करेगा, जिससे देश की एविएशन इंडस्ट्री को नई मजबूती मिलेगी। इस एमआरओ हब के विकसित होने से एयरलाइंस कंपनियों को अब अपने विमानों को विदेश भेजने की आवश्यकता कम होगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि परिचालन लागत में भी भारी कमी आएगी। भारत में ही विश्वस्तरीय मेंटेनेंस

सुविधाएं उपलब्ध होने से देश वैश्विक एविएशन सर्विस मार्केट में प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

**रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को मिलेगा
बढ़ावा**

यह परियोजना स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। युवाओं को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एविएशन टेक्नोलॉजी और तकनीकी सेवाओं में प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश-प्रोत्साहन नीतियों के चलते प्रदेश में इस तरह की हाईटेक परियोजनाओं का तेजी से विकास हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए अवसरों का केंद्र बनता जा रहा है।

**एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब बनने की दिशा
में बड़ा कदम**

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक समग्र एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एमआरओ सुविधा इस विजन का अहम हिस्सा है, जो प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमआरओ सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण स्तंभ

बताते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत न केवल अपने विमानों की सर्विसिंग करेगा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

भारत में तेजी से उभर रहा है एमआरओ सेक्टर

नोएडा एयरपोर्ट में यह सुविधा स्थापित होने के साथ ही भारत में एमआरओ सेक्टर तेजी से विकास करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक इसका बाजार 5.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत सरकार की एमआरओ नीति 2021 के तहत करें में रियायत और भूमि पट्टे में छूट देकर घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत को वैश्विक एमआरओ हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी आई है।

यूएसए है अग्रणी देश

वैश्विक स्तर पर एमआरओ सुविधाएं प्रमुख विमान हब का अहम हिस्सा हैं, जहां अमेरिका सबसे अधिक एमआरओ कंपनियों के साथ अग्रणी है, जबकि यूके, फ्रांस व जर्मनी यूरोप के प्रमुख केंद्र हैं। एशिया-प्रशांत में सिंगापुर, चीन, भारत और फिलीपींस, जबकि मध्य पूर्व में यूएई महत्वपूर्ण एमआरओ हब के रूप में उभर रहे हैं।





लखनऊ के गोसाईगंज के पास, रात भर हुई बारिश के बाद एक किसान अपनी गेहूं की फसल की देखभाल कर रहा है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध का दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर





अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच युद्ध को एक महीना पूरा हो चुका है। अभी तक इसके समाप्त होने के आसार नहीं नजर आते। दोनों पक्षों ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें पूरा करना उन दोनों के लिए लगभग नामुमकिन ही है। अमेरिका की 15 बिंदुओं वाली योजना में ईरान से ऐसी गारंटी मांगी गई है जो उसे शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में भविष्य के हमलों से बचाव करने में असमर्थ बना देगी। इसके जवाब में ईरान ने भी शर्तें रखीं, जैसे प्रतिबंध हटाना, नेतृत्व करने वालों की हत्याओं को रोकना और भविष्य में अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ गारंटी देना।

पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किये और सऊदी अरब द्वारा समझौता कराने के प्रयासों के बावजूद दोनों पक्षों का अड़ियल रवैया वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी आर्थिक बोझ डालने वाला है। पहले से ही एशियाई देश, जो पश्चिम एशियाई जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर हैं, मुद्रास्फीति के प्रभाव और ईंधन की कमी से उत्पन्न कठिनाइयों को नियंत्रित करने के लिए जूझ रहे हैं, जिसका उनकी अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त पर दीर्घकालिक प्रतिकूल असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, तेल विपणन कंपनियों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 10 रुपये प्रति लीटर कम करना, भारतीय सरकारी राजस्व को वार्षिक आधार पर 1.2 लाख करोड़ रुपये से 1.7 लाख करोड़ रुपये तक घटा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक कठिनाई सामने है, क्योंकि प्रतिशोधी हमलों की दोबारा शुरुआत और यमन के हथियारों द्वारा इजरायल के खिलाफ अप्रत्याशित आक्रामकता ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। यह नया मोर्चा स्वेज नहर और लाल सागर होकर चलने वाले एक अन्य प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग को खतरे में डाल सकता है। होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री तेल और गैस व्यापार का एक चौथाई हिस्सा होता है और यह पश्चिम एशियाई जीवाश्म ईंधन उत्पादकों का मुख्य मार्ग है। अब तक ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में खनन और नाकेबंदी ने तेल की कीमतों को 73 डॉलर प्रति बैरल (बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड) से बढ़ाकर 110-119 डॉलर तक पहुंचा दिया है, साथ ही इसकी भारी कमी भी पैदा की है। पूर्वी एशिया पर इसका विशेष रूप से गंभीर असर पड़ा है क्योंकि 80 से 90 फीसदी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी

मार्ग से आते हैं। सऊदी अरब ने नाकेबंदी का सामना करने के लिए अपने पूर्व-पश्चिम स्थलीय पाइपलाइन से लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक तेल प्रवाह बढ़ाने की कोशिश की, जिससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हुआ। लेकिन अब वह मार्ग भी खतरे में है। स्वेज नहर/लाल सागर दुनिया के कंटेनर यातायात का एक-तिहाई हिस्सा संभालता है, और दुनिया पहले ही 2023 और 2024 में हूती व्यवधानों का असर देख चुकी है। जहाजों को अफ्रीका के पश्चिमी तट से नीचे और केप ऑफ गुड होप के चारों ओर लंबा मार्ग लेना पड़ा, जिससे शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम सहित, तेजी से बढ़ गई और वैश्विक मुद्रास्फीति दबाव तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और गहरा गया। यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान की प्रतिक्रियाओं और क्षमताओं का गंभीर रूप से गलत आकलन किया है। ईरान के राजनीतिक और सुरक्षा नेतृत्व की हत्या ने भी उसे आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसके विपरीत, उसने बार-बार अपने विरोधियों को चकमा देने वाले विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल किया है। दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों से एक महीने तक ईरान पर हमले करने के बावजूद, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि उसके मिसाइल भंडार और ड्रोन क्षमता का केवल लगभग एक-तिहाई ही नष्ट हुआ है। बाकी की स्थिति को लेकर वे अनिश्चित हैं। एक ऐसा देश जिसने ठीक इसी परिस्थिति के लिए योजना बनाई है और जिसे लंबे युद्ध और कठिनाइयों का अनुभव है, उसके लिए लंबा, असमान और थकाऊ युद्ध कोई नुकसान नहीं माना जाता।

औद्योगिक क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं प्रभावी निगरानी के लिए ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली होगी लागू



लखनऊ-। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की 50वीं बोर्ड बैठक लोक भवन, लखनऊ में अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप आयोजित इस बैठक में औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना सुदृढीकरण एवं निवेश प्रोत्साहन से जुड़े कुल 34 प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में विकास एवं अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के चयन

को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से सिविल, विद्युत एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी।

कम्पिल कताई मिल, मऊ आइमा, बहादुरगंज, सलेमपुर एवं बाराबंकी के औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं बलिया, हाथरस, फतेहपुर, बाराबंकी एवं चित्रकूट के औद्योगिक क्षेत्रों के प्रस्तावों पर विचार करते हुए संशोधन के निर्देश दिए गए तथा संशोधित तलपट (लेआउट) मानचित्र को स्वीकृति दी गई।

भूमि बैंक को सुदृढ करने हेतु नीतिगत संशोधन के निर्देश दिए गए। साथ ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए संशोधित योजना तैयार करते हुए प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया।

एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत यह तय किया गया कि आवंटन योग्य भूमि का 75 प्रतिशत आवंटन पूर्ण होने के पश्चात शेष 25 प्रतिशत भूमि का आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह भी

निर्देशित किया गया कि प्रचलित परियोजनाओं में विकास कार्यों को जारी रखते हुए समानांतर रूप से आवंटन प्रक्रिया संचालित की जाए,

त। कि
निवेश में तेजी
लाई जा सके।

यूपीसीडा की 50वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति

लाई जा सके।

सहारनपुर एवं बदायूं में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में निर्देश दिए गए कि अधिग्रहण से पूर्व सड़क संपर्क (रोड कनेक्टिविटी) एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए, जिससे औद्योगिक इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास हेतु शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तपोषण का प्रभावी उपयोग करते हुए एक वर्ष के भीतर बुनियादी सुविधाओं का तीव्र विकास सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित कर एक माह के भीतर उनका निस्तारण किया जाए।

अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि यूपीसीडा का लक्ष्य केवल औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक विश्वस्तरीय औद्योगिक ईकोसिस्टम का निर्माण करना है, जहां तकनीक, पारदर्शिता और दक्षता के आधार पर उद्यमियों को बेहतर वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि ड्रोन आधारित निगरानी, डिजिटल सेवाएं और पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया जैसे निर्णय प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में तेजी से अग्रसर करेंगे। अंत में अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सहारनपुर और बदायूं जैसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के दौरान कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि औद्योगिक विकास को दीर्घकालिक मजबूती मिल सके।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूपी में निवेश को मिलेगा बड़ा बूस्ट

रोजगार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का
मेगा हब बनेगा यूपी का जेवर

निर्यात को मिलेगी रफ्तार, यमुना
एक्सप्रेसवे क्षेत्र बनेगा ग्लोबल निवेश और
मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र

औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में उभर रहा जेवर,
तेजी से बढ़ रहे निवेश प्रस्ताव

1 लाख से अधिक रोजगार, हजारों करोड़ की
आर्थिक गतिविधि का अनुमान

जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में निवेश, उद्योग और व्यापार के नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह एयरपोर्ट न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश के मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर बताते हुए कहा कि यह परियोजना निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोलेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे बना निवेश का नया इंजन

यमुना एक्सप्रेसवे और इसके आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव आने शुरू हो चुके हैं। एयरपोर्ट के कारण यह क्षेत्र तेजी से एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है, जहां देश-विदेश की कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं। एयरपोर्ट के आसपास मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, डेटा सेंटर, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल और टॉय पार्क जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में क्षेत्र में सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखे जाने से हाईटेक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। भविष्य में यहां फिनटेक सिटी जैसे अत्याधुनिक प्रोजेक्ट भी विकसित किए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र टेक्नोलॉजी और उद्योग का प्रमुख केंद्र बनेगा। निर्यात को मिलेगी नई रफ्तार

मल्टी मोडल कार्गो हब बनने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को 'लैंडलॉकड' स्थिति से बाहर निकालकर वैश्विक बाजार से सीधे जोड़ देगा। इससे प्रदेश के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंच सकेंगे और निर्यात को नई गति मिलेगी। इस एयरपोर्ट परियोजना से लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही करीब 60,000 करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होने का अनुमान है। सरकार को इससे लगभग 2000 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हो सकता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा।

दीर्घकालिक विकास का मजबूत आधार

इस परियोजना का कंसेशन पीरियड 40 वर्षों का है। अनुमान है कि वर्ष 2061-62 तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त होगी, जो इसकी दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। कुल मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि निवेश, उद्योग, निर्यात और रोजगार का एक समग्र विकास मॉडल बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में यह परियोजना प्रदेश को आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।



कार्गो हब बनाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्लोबल ट्रेड गेटवे, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार

जेवर । उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब केवल यात्री सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह देश के सबसे बड़े कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में भी उभरने जा रहा है। एयरपोर्ट के पास निर्मित डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और विशेष कार्गो रूट इस क्षेत्र को ग्लोबल ट्रेड गेटवे बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में शामिल यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है।

डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल से बढ़ेगी क्षमता

एयरपोर्ट परिसर में एक अत्याधुनिक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल विकसित किया गया है, जिसकी प्रारंभिक क्षमता लगभग 20 लाख मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। भविष्य में इसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, शुरुआती चरण में लगभग 2.5 लाख टन प्रति वर्ष कार्गो संचालन की क्षमता विकसित की गई है, जिसे आगे बढ़ाकर करीब 15 लाख टन प्रति वर्ष तक विस्तारित किया जाएगा। लगभग 80 हजार वर्गमीटर में फैले इस कार्गो क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लॉजिस्टिक्स सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

मल्टी मॉडल कार्गो हब का हो रहा विकास

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक मल्टी मॉडल कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां वायु मार्ग, सड़क और संभावित रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से माल परिवहन को आसान बनाया जाएगा। डेडिकेटेड कार्गो रूट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे औद्योगिक इकाइयों से सीधे एयरपोर्ट तक माल की तेज और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।

उद्योगों को मिलेगा सीधा लाभ

यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनुफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, वेयरहाउसिंग और फार्मा सेक्टर को इस कार्गो हब से सीधा लाभ मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास स्थापित उद्योगों के उत्पाद अब तेजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकेंगे, जिससे निर्यात को

जाएगी। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और उद्योगों को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस तरह की सुविधाओं से उत्तर प्रदेश जस्ट-इन-टाइम सप्लाई मॉडल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे वैश्विक कंपनियों का भरोसा भी बढ़ेगा।

ग्लोबल ट्रेड गेटवे के रूप में उभरता उत्तर प्रदेश

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह कार्गो हब उत्तर प्रदेश को 'लैंडलॉक' स्थिति से बाहर निकालते हुए सीधे वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे न केवल निर्यात-आयात को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

नई गति मिलेगी और उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। सप्लाई चेन होगी मजबूत, समय और लागत में कमी

डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल और विशेष रूट के कारण लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया अधिक सुगम और समयबद्ध हो



आजीविका के लिए संघर्ष करने वाली महिला ने दुग्ध उत्पादन से दो साल में कमाए 67 लाख

योगी सरकार की योजना का लाभ पाकर बन गई सफल उद्यमी

मिलिए सोनभद्र की लखपति दीदी से, आज संयुक्त परिवार के 14 लोगों की सम्भाल रही जिम्मेदारी

एक साहसी महिला की कहानी उन ग्रामीण महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा जो आगे बढ़ने का देखती हैं सपना

परिवार संभालने के साथ ही बच्चों को उपलब्ध करा रही हैं बेहतर शिक्षा

लखनऊ- कभी आजीविका के लिए संघर्ष करने वाली सोनभद्र की विनीता आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही महिला सशक्तीकरण की योजनाओं के सहारे सफलता का नया चेहरा बनकर उभरी हैं। दुग्ध उत्पादन को आजीविका का आधार बनाकर उन्होंने सिर्फ दो वर्षों में 67 लाख रुपये की कमाई की और यह साबित कर दिया कि सही सरकारी सहयोग, बाजार और मेहनत मिल जाए तो गांव की महिलाएं भी आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिख सकती हैं।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़कर उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। आज वे परिवार संभालने के साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा भी उपलब्ध करा रही हैं।

पहले निजी डेयरियों पर थी निर्भरता

स्नातक तक पढ़ीं विनीता 14 सदस्यीय संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभा रही थीं। पति अविनाश के साथ मिलकर वे 10-12 पशुओं के जरिए कार्य करती थीं, लेकिन निजी डेयरियों पर निर्भरता के कारण उन्हें समय पर और उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इससे आय सीमित थी।

संघर्ष से निकली उम्मीद की राह

दिन-रात मेहनत के बावजूद जब हालात नहीं बदले, तब विनीता ने काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ने का फैसला किया। इससे उन्हें उचित मूल्य, समय पर भुगतान और प्रशिक्षण की सुविधा मिली। यही वह



मोड़ था, जिसने उनके जीवन को नई दिशा दी। दो साल में बनी 'लखपति दीदी'

विनीता ने वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया। पशुओं की संख्या बढ़ाई और उत्पादन में बड़ा इजाफा किया। आज उनके पास 40 से अधिक दुधारू पशु हैं और वे 'लखपति दीदियों' में शामिल हो चुकी हैं। महज दो वर्षों में 67 लाख रुपये की आय अर्जित कर उन्होंने ग्रामीण महिला सशक्तीकरण का नया उदाहरण पेश किया है।

हजारों महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी पूर्वांचल के सात जिलों में 46 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार और सशक्तीकरण से जोड़ रही है। विनीता कहती हैं कि

काशी मिल्क और स्वयं सहायता समूह ने मुझे न केवल आर्थिक मजबूती दी, बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया भी दिया।

योजनाओं का जमीनी असर

योगी सरकार की महिला सशक्तीकरण और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का असर अब गांवों में साफ दिख रहा है।

विनीता जैसी महिलाएं न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन दे रही हैं, बल्कि समाज में बदलाव की अगुआ बन रही हैं।

सोनभद्र की विनीता की यह कहानी बताती है कि अगर सही मंच, उचित मूल्य और सरकारी योजनाओं का साथ मिल जाए तो ग्रामीण महिलाएं भी सफलता की नई इबारत लिख सकती हैं।

उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस से सजा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रतीक चिन्ह

**नीला-हरा ग्रेडिएंट परंपरा और
आधुनिकता का संगम,
तकनीक, कनेक्टिविटी और
पर्यावरण का संदेश**

जेवर । नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी ब्रांड पहचान को खास और वैश्विक स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को अपने प्रतीक (लोगो) के रूप में अपनाया है। यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन को दर्शाती है, जिसमें विकास के साथ सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरणीय संतुलन को भी समान महत्व दिया जा रहा है। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होने के साथ-साथ समृद्ध परंपरा और प्रकृति का प्रतीक है। एयरपोर्ट के लोगो में इसे शामिल करना राज्य की विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की एक सार्थक पहल है, जो योगी सरकार के विकास के साथ विरासत के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।

डिजाइन में तकनीक और इको-फ्रेंडली सोच का

मेल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोगो को पतली और एकीकृत रेखाओं से तैयार किया गया है, जो गति, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संकेत देती हैं। नीले-हरे रंग का ग्रेडिएंट तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन को दर्शाता है, जो योगी आदित्यनाथ की ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति के अनुरूप है।

उड़ान में छिपा विकास और सकारात्मकता का संदेश

लोगो में उड़ता सारस प्रगति, आत्मविश्वास और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश का प्रतीक है। यह राज्य को एक वैश्विक निवेश और कनेक्टिविटी हब बनाने के विजन को भी दर्शाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह प्रतीक न केवल इसकी ब्रांडिंग को मजबूत कर रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान को भी अलग और प्रभावी बना रहा है। यह एयरपोर्ट अब केवल एक परिवहन केंद्र नहीं, बल्कि संस्कृति, आधुनिकता और सतत विकास का प्रतीक बनकर उभर रहा है।

सारस की
उड़ान बनी
नोएडा
इंटरनेशनल
एयरपोर्ट की
पहचान



छोटे उद्योगों पर दोहरी मार

पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी वर्किंग कैपिटल की मांग, बैंकों की बढ़ी टेंशन

पश्चिम एशिया युद्ध के कारण बढ़ती इनपुट लागत और सप्लाई चेन में रुकावट से छोटे उद्योगों में वर्किंग कैपिटल लोन की मांग तेजी से बढ़ रही है

पश्चिम एशिया में संघर्ष एक महीने से अधिक खिंचने के कारण लघु, सूक्ष्म और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की कार्यशील पूंजी ऋण की मांग बढ़ गई है। निर्धारित लागत के भुगतान और प्राप्ति में देर होने की वजह से छोटे उद्योगों के नकदी प्रवाह पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे बैंकों से कर्ज की मांग बढ़ गई है।

बैंकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का सबसे अधिक असर एमएसएमई पर पड़ने की आशंका है। वित्त वर्ष 2026 की जनवरी-मार्च तिमाही में इसका असर सीमित रहा है मगर वित्त वर्ष 2027 में बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर इसका दबाव दिखाई देगा। बैंकों का कहना है कि यह क्षेत्र प्रमुख चिंता का विषय बन सकता है।

निजी क्षेत्र के एक बैंक के वरिष्ठ बैंकर ने कहा, 'कुछ हद तक दबाव अभी से दिख रहा है। निश्चित रूप से ऋण की मांग बढ़ी है। संभवतः यह वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए है। हालांकि साल के समापन के समय भी अक्सर ऐसे ही रुझान देखे जाते हैं। ऐसे में प्रभाव को स्पष्ट रूप से अलग करना मुश्किल है।' उन्होंने कहा, 'हमें थोड़ा इंतजार करना और देखना होगा कि आगे किस तरह के हालात बनते हैं।'

पश्चिम एशिया युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से कुछ क्षेत्रों पर गंभीर असर पड़ा है। इसमें गुजरात के मोरबी में सिरेमिक क्लस्टर शामिल है। कांच और चूड़ी उद्योग पर भी व्यापक असर पड़ा है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया के बाजारों पर निर्भर रहने वाले चावल निर्यातक भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उर्वरक जैसे क्षेत्रों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी क्षेत्र के बैंक के एक अन्य वरिष्ठ बैंकर ने कहा, 'यदि आप इसे देखें तो कार्यशील पूंजी की मांग बहुत अधिक नहीं रही है। मगर मुझे लगता है कि यह अंततः काफी बढ़ सकती है। यदि मैं अपने पोर्टफोलियो को देखू तो फिलहाल उपयोगिता ज्यादा नहीं बढ़ी है।'

जब कामकाज का स्तर कम होता है तो कार्यशील



पूंजी की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब गतिविधियां सुस्त होती हैं तो नियत लागत को पूरा करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा कि इस नजरिये से देखें तो, 'जो कुछ मैं सुन रहा हूँ उसके आधार पर कुछ दबाव हो सकता है।' उन्होंने आगाह किया कि अगले 6 से 12 महीनों में कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा, 'मौजूदा हालात का पूरा असर शायद अप्रैल के आखिर या मई में दिखाई देगा क्योंकि ऐसे असर सामने आने में थोड़ा समय लगता है।' बैंकों के अनुसार कच्चे माल, माल

ढुलाई और शिपिंग जैसे इनपुट लागत में वृद्धि चुनौती हो सकती है। साथ ही डीजल की कीमतें बढ़ने से घरेलू परिवहन लागत में संभावित वृद्धि हो सकती है। पैकेजिंग सामग्री की लागत पहले ही बढ़ चुकी है और प्लास्टिक तथा रसायन जैसे कच्चे तेल से जुड़े उद्योगों में लागत का दबाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की मांग बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए यदि इनपुट लागत 20 से 30 फीसदी बढ़ती है तो भले ही उत्पादन की मात्रा कम हो जाए मगर कुल पूंजी की आवश्यकता बढ़ सकती है।

युद्ध वहां, बर्बादी यहां! पश्चिम एशिया की जंग ने ओडिशा के प्लास्टिक उद्योग की तोड़ी कमर, कारखानों में सन्नाटा



पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे माल की कीमतों में 75% उछाल आने से बालासोर का प्लास्टिक हब ठप हो गया है, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 205 किलोमीटर दूर बालासोर में गणेश्वरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाले कारखाने में ठेके पर काम करने वाले 35 वर्षीय मजदूर रतन सिंह को इन दिनों बेरोजगारी जैसी हालात से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'महज एक महीना पहले हमारे पास थोड़ा भी आराम करने का समय नहीं था। मगर अब मशीनें काफी समय तक बंद रहती हैं। फैक्टरी सुपरवाइजर

बताते हैं कि कच्चा माल न होने के कारण काम नहीं है। हमें स्थिति में सुधार होने तक इंतजार करने के लिए कहा गया है। अब लगभग 15 दिन हो चुके हैं और मैं बेरोजगार हूँ।'

करीब 70 एकड़ क्षेत्र में फैला गणेश्वरपुर औद्योगिक क्षेत्र तटीय जिले के सात प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केंद्रों में शामिल है। यहां प्लास्टिक, पॉलिमर और इससे संबद्ध क्लस्टर में लगभग 20 एमएसएमई इकाइयां परिचालन में हैं। इन इकाइयों में पॉलिप्रोपिलीन आधारित घरेलू उत्पादों, बैग, पाइप और फिटिंग्स के सामानों का उत्पादन होता है।

हजारों मील दूर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट के अवरुद्ध होने का प्रभाव इस औद्योगिक पट्टी के कारखानों में सन्नाटों के रूप में दिखने लगा है। भले ही यहां के मजदूरों ने कभी कच्चे तेल का बैरल तक न देखा हो लेकिन इसकी

वजह से उन्हें रोजगार का नुसान हो रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्य दिनों में 1,500 से अधिक होती थी जो अब घटकर 800 से भी कम रह गई है।

रतन जैसे श्रमिकों को रोजाना अथवा पाली के आधार पर भुगतान किया जाता है। उनके लिए पश्चिम एशिया संकट का मतलब तत्काल मजदूरी का नुकसान है। अपने कारखाने के समीप एक चाय की दुकान पर बैठे रवींद्र साहू ने कहा, 'अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी कमाई भी नहीं होगी। मगर पारिवारिक खर्च तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा कब तक चलेगा? अगर यही स्थिति एक सप्ताह और रही तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे।'

औद्योगिक क्लस्टर के मध्य में स्थित प्लास्टिक हाउसवेयर विनिर्माण इकाई जगदम्बा पॉलिमर्स लिमिटेड के भीतर संकट का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। वहां की इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीनें एक-एक करके बंद

हो रही हैं। वहां की बाल्टियां, मग आदि सामान्य तौर पर ताजा उत्पादों से भरे होते थे लेकिन फिलहाल वे खाली नजर आ रहे हैं। बाथ सेट, कैसरोल, बच्चों के उत्पाद आदि के आधे-अधूरे तैयार माल बंद पड़े कन्वेयर बेल्ट के पास बिखरे पड़े हैं। उत्पादन की रफ्तार बेहद सुस्त पड़ चुकी है।

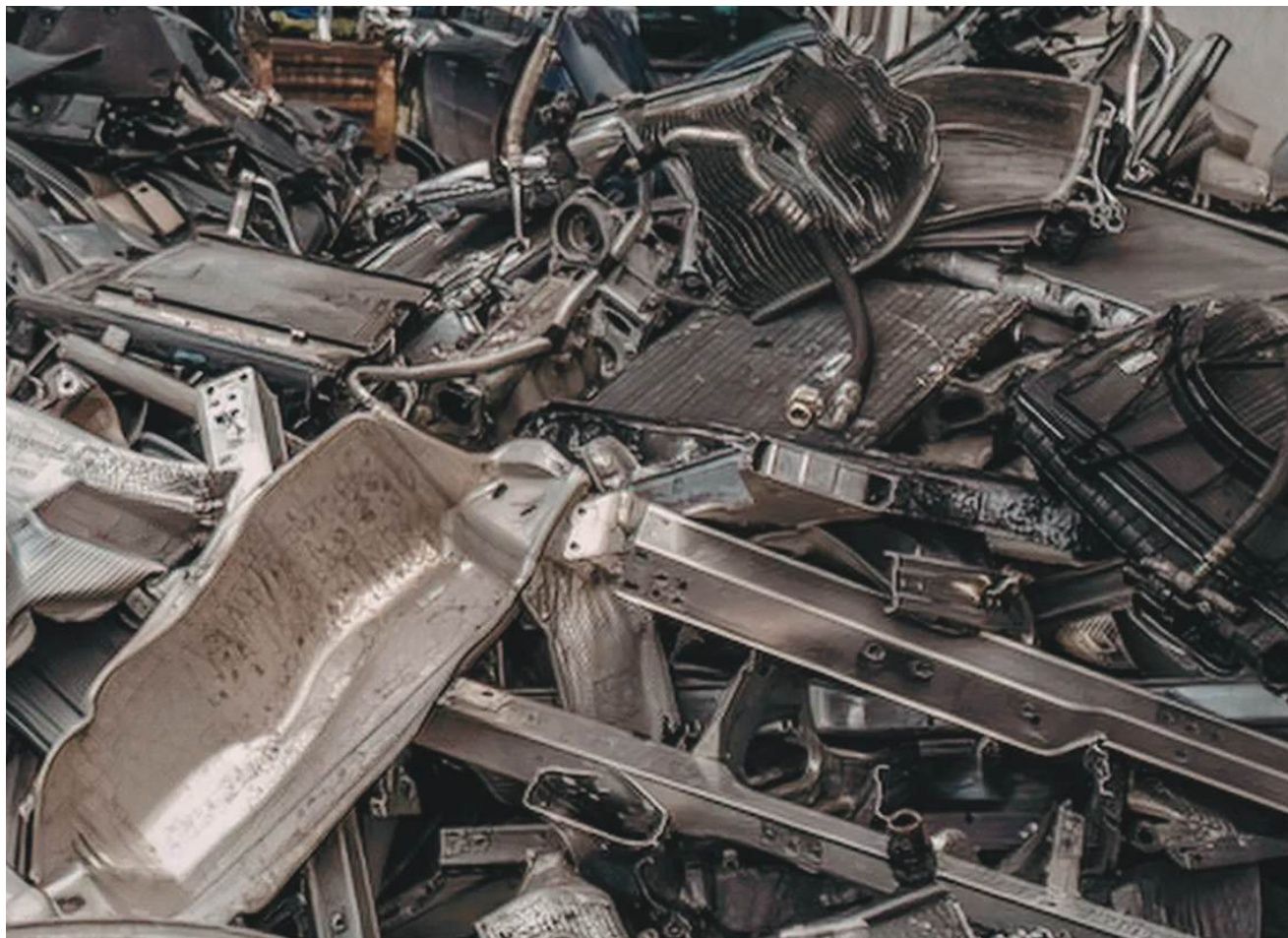
जगदम्बा ओडिशा में एक बड़े इंजेक्शन मोल्डिंग कारखाने का संचालन करती है जो पूर्वी भारत में सबसे बड़ा है। कंपनी अपने उत्पादों के लिए शीर्ष ब्रांडों में

‘उत्पादन में लगभग 70 फीसदी की कमी आई है। एक छत के तले 10 उत्पादन लाइनों में से केवल 2 ही चालू हैं। हम मांग के अनुसार मशीनों को नए सिरे से संचालित कर रहे हैं क्योंकि हम कच्चे माल की लागत काफी अधिक होने पर उत्पादों का ढेर नहीं लगा सकते। आय के तत्काल नुकसान से भी अधिक खतरनाक है अनिश्चितता की स्थिति।’

भारत के पास पेट्रोरसायन की घरेलू उत्पादन क्षमता काफी है लेकिन पॉलिमर की बढ़ती मांग को पूरा करने

बेतहाशा वृद्धि वास्तव में अभूतपूर्व है। ऐसे में हमारे पास उत्पादन को कम करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।’

कुछ ही किलोमीटर दूर प्लास्टिक पाइप एवं फिटिंग्स बनाने वाली इकाई हरि प्लास्ट में भी बड़े पैमाने पर व्यवधान दिख रहा है। वहां की लंबी एक्सट्रूजन लाइनें पहले लगातार चलती रहती थीं, फिलहाल वे बंद हैं और उनके फ्रेम खाली हैं। वहां की 12 उत्पादन लाइनों की मासिक स्थापित क्षमता 650 टन पॉलिविनाइल



शुमार है और 12 से अधिक राज्यों में उसकी मौजूदगी है। उसके कारखाने में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह है।

वहां एक उत्पादन लाइन पर जग (जूस के लिए) पर स्टिकर लगाते हुए एक मजदूर राजेंद्र मंडल ने कहा, ‘युद्ध वहां हो रहा है लेकिन उससे यहां हम लोगों को नुकसान हो रहा है। पहले

सभी मशीनें उत्पादन करती थीं। मगर अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। हमें कच्चे माल की कमी के कारण मशीनें बंद होने से नौकरी जाने की चिंता सता रही है।’ कारखाना प्रबंधकों ने स्वीकार किया कि उत्पादन धीमा होने का असर सबसे पहले ठेका मजदूरों पर पड़ता है। उत्पादन प्रभारी कार्तिक चंद्र कर ने कहा,

के लिए कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता काफी अधिक है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के बाधित होने पर घरेलू विनिर्माताओं को मूल्य के झटके और आपूर्ति में कमी यानी दोहरी मार का सामना करना पड़ता है।

जगदम्बा पॉलिमर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक चंद्र प्रकाश भरतिया ने कहा कि भारतीय प्लास्टिक प्रॉसेसिंग उद्योग वैश्विक कच्चे तेल के परिवहन के प्रति काफी संवेदनशील है। उन्होंने कहा, ‘पॉलिमर नैफ्था एवं अन्य कच्चे तेल उत्पाद से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। इसलिए भू-राजनीतिक अस्थिरता की सूरत में इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। पॉलिमर और पीईटी रेजिन की कीमतों में 75 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। इतनी कम अवधि में हुई

क्लोराइड (पीवीसी), क्लोरिनेटेड पॉलिविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी), उच्च घनत्व वाली पॉलिथीन (एचडीपीई) और मध्यम घनत्व वाली पॉलिथीन (एमडीपीई) पाइपों के उत्पादन की है। मगर उनमें से फिलहाल 2 लाइन ही चालू हैं जो सिंचाई, पेयजल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाली पाइपों का सीमित उत्पादन कर रही हैं।

हरि प्लास्ट के उपाध्यक्ष (तकनीकी) तरुण रे ने कहा, ‘फैक्टरी आम तौर पर 300 से अधिक तरह की पाइप एवं फिटिंग्स का उत्पादन करती है। मगर अब उत्पादन घटकर महज 10 से 12 प्रकार के उत्पादों तक सीमित रह गया है। सामान्य दिनों में वहां तीन पालियों में 350 से अधिक कर्मचारी काम करते थे जो घटकर

अब महज 60 रह गए हैं। कच्चे माल की कीमतों में असामान्य तौर पर वृद्धि हुई है और आपूर्ति के मोर्चे पर अनिश्चितता बरकरार है। ऐसे में सभी लाइनों को चलाने का मतलब भारी नुकसान होगा।

गनेश्वरपुर में नियो ट्यूब्स के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र प्रसाद दास अपने कारखाने में बंद पड़ी मशीनों की ओर इशारा करते हुए कहा, 'हमारे पास पांच एक्सट्रूजन लाइनें हैं जिनमें से अब केवल एक चालू है। महज एक महीना पहले हम लगभग 100 टन प्रति महीना उत्पादन करते थे जो अब घटकर 20 टन से भी कम रह गया है। पानी की टंकियों का उत्पादन करने वाली हमारी इकाई बंद हो गई है। हम ऐसे अस्थिर बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।'

कुछ इकाइयां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। वेलेंटिना पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निकुंज छोटाराय ने कहा कि उनकी फैक्टरी कई दिनों से बंद है। भुवनेश्वर के इस विनिर्माता ने कहा, 'कीमत अथवा आपूर्ति के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कच्चे माल की कीमतों में तेजी के लिहाज से उत्पादों के दाम को अचानक बढ़ाना मुश्किल है। ऐसे में कारखाने को चलाने से रोजाना केवल नुकसान ही होगा।'

यहां तक कि अपेक्षाकृत बड़े निर्माता भी इससे अछूते नहीं हैं। उच्च क्षमता और बेहतर वित्तीय बफर वाली कंपनियों ने भी उत्पादन में 50 से 70 फीसदी की कमी की है। कोलकाता की कंपनी ओरि प्लास्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी पीके दवे ने कहा, 'हमने नुकसान को कम करने के लिए उत्पादन को तर्कसंगत बनाया है। हमने उत्पाद के दाम भी बढ़ाए हैं लेकिन मांग कम हो गई है। फिलहाल बाजार में काफी अस्थिरता दिख रही है। हम स्थिति नजर रख रहे हैं।' कंपनी की बालासोर इकाई की मासिक स्थापित क्षमता 1,200 टन है।

प्लास्टिक इकाइयां क्यों हो रहीं प्रभावित

प्लास्टिक उत्पादों को कच्चे माल की एक श्रृंखला से तैयार किया जाता है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से शुरू होती है। ऐसे में यह उद्योग वैश्विक ऊर्जा बाजारों के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाता है। बुनियादी स्तर पर कच्चे तेल की रिफाईनिंग के जरिये नैफ्था का उत्पादन किया जाता है जबकि प्राकृतिक गैस से ईथेन और प्रोपेन प्राप्त होते हैं।

इन फीडस्टॉक्स की प्रॉसेसिंग पेट्रोसायन संयंत्रों में की जाती है जिससे एथिलीन और प्रोपलीन जैसे प्रमुख उत्पाद तैयार होते हैं। उसके बाद इन उत्पादों को एचडीपीई, एलएलडीपीई, पीपी, पीवीसी और पीईटी रेजिन जैसे पॉलिमर में परिवर्तित किया जाता है जिनका उपयोग प्लास्टिक विनिर्माता पाइप और कंटेनर से लेकर फर्नीचर और पैकेजिंग तक तमाम उत्पाद बनाने में करते हैं।

इसके अलावा प्लास्टिक को अपेक्षित शक्ति,

लचीलापन, रंग और स्थायित्व देने के लिए प्लास्टिसाइजर, स्टेबलाइजर, पिगमेंट और फिलर जैसे विभिन्न घटकों को मिलाया जाता है। आयातित पेट्रोसायन इनपुट पर भारत की अत्यधिक निर्भरता समस्या को जटिल बनाती है। एचडीपीई की कीमतें 28 फरवरी को लगभग 91,452 रुपये प्रति टन थीं जो 1 अप्रैल तक करीब 75 फीसदी बढ़कर 1.6 लाख रुपये हो गईं।

इसी प्रकार एलएलडीपीई की कीमतें करीब 77 फीसदी बढ़कर 90,952 रुपये से 1.61 लाख रुपये, पीवीसी की कीमतें करीब 30 फीसदी बढ़कर 89,000 रुपये से 1.16 लाख रुपये, पीपी के दाम 50.5 फीसदी बढ़कर 1,00,384 रुपये से 1.51 लाख रुपये और पीईटी रेजिन की कीमतें 92,000 रुपये से 52 फीसदी बढ़कर 1.4 लाख रुपये हो गईं।

प्लास्टिक उत्पादों की कुल लागत में कच्चे माल की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी होती है। ऐसे में कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल का विनिर्माताओं पर सीधा और गंभीर प्रभाव पड़ता है। अधिकतर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मामूली मार्जिन और लंबी अवधि के आपूर्ति अनुबंधों पर काम करते हैं। ऐसे में लागत में अचानक हुई वृद्धि का बोझ ग्राहकों के कंधों पर डालना भी मुश्किल हो जाता है।

बड़े परिवेश को खतरा

उत्पादन पर प्रभाव काफी तेज और गंभीर रहा है। प्लास्टिक पाइप एवं फिटिंग विनिर्माताओं के लिए यह दोहरी मार साबित हुई है क्योंकि उन्हें कच्चे माल की कीमतों में उछाल और कमजोर मांग से जूझना पड़ रहा है। पॉलिमर की लागत में ऐसे समय में जबरदस्त वृद्धि हुई है जब सरकारी क्षेत्र की मांग काफी गिर चुकी है।

वित्त वर्ष 2026 के लिए जल जीवन मिशन के तहत बजट आवंटन को काफी कम कर दिया गया है। खर्च में सुस्ती, कार्यान्वयन में देरी और परियोजना में कथित अनियमितताओं के कारण 67,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अनुमान को संशोधित अनुमान में घटाकर 17,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं से एचडीपीई और पीवीसी पाइपों की मांग को बढ़ावा मिलता था।

हरि प्लास्ट और ओम पाइप्स जैसी इकाइयां बड़े पैमाने पर पाइप आपूर्ति के लिए सरकारी अनुबंधों पर काफी निर्भर हैं। मगर आवंटन में कमी के कारण उनके अनुबंध पहले ही रद्द हो चुके हैं और भुगतान में देरी हो रही है। एक विनिर्माता ने कहा, 'पहले जल जीवन मिशन के लिए मांग पूरे साल रहती थी। मगर अब वह सहारा भी चला गया है। हम बिना ऑर्डर के और कच्चे माल की भारी लागत वाली एक अजीब स्थिति से जूझ रहे हैं।' केवल ओडिशा में प्लास्टिक उत्पादों से संबंधित 56 इकाइयों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। उद्योग संघों का मानना है कि प्लास्टिक उत्पादों की छोटी

विनिर्माण इकाइयों में से 40 फीसदी से अधिक बंद हो चुकी हैं। शेष मझोली एवं बड़ी इकाइयों ने अपने संचालन में भारी कटौती की है।

ओडिशा प्लास्टिक पाइप्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संग्राम दास ने कहा कि स्थिति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, 'उत्पादन पूरी तरह से अव्यवहार्य हो चुका है। इसके बावजूद अगर हम अपनी इकाइयां चलाना चाहें तो कच्चा माल या तो उपलब्ध नहीं है या फिर उसकी कीमत हमारी क्षमता से बाहर है। तीन चौथाई से अधिक इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो हमें कुछ महीनों के लिए अपने नियमित कर्मचारियों को बिना काम 50 फीसदी वेतन देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।' दास हरि प्लास्ट के प्रबंध निदेशक भी हैं।

भारत का प्लास्टिक प्रॉसेसिंग क्षेत्र काफी विशाल और अर्थव्यवस्था से गहराई तक जुड़ा हुआ है। यहां के लगभग 50,000 उद्यमों में 30,000 पंजीकृत प्रॉसेसिंग इकाइयां हैं। इनमें से 85 फीसदी एमएसएमई हैं जो सीधे तौर पर लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देते हैं और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र करीब 2.2 लाख टन पॉलिमर की खपत करता है और निर्यात में सालाना 12.5 अरब डॉलर का योगदान देता है। मौजूदा व्यवधान एक अप्रत्याशित झटके के रूप में सामने आया है जबकि भारत 2030 तक 25 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रख रहा है।

मुख्यमंत्री ने बिहार दिवस समारोह 2026 का दीप प्रवर्तित कर किया उद्घाटन

पटना- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह 2026 का दीप प्रवर्तित कर एवं गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया।

समारोह में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉ० बी० राजेन्द्र ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया।

बिहार के 114 वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम की थीम 'उन्नत बिहार, उवल बिहार' रखी गयी है।

मुख्यमंत्री ने बिहार दिवस समारोह-2026 के उद्घाटन से पूर्व पटना के ऐतिहासिक गाँधी मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों से संबंधित लगाई गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन

प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं पर आधारित लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ० उदयकांत ने पुष्प गुच्छ भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के पवेलियन में लगायी गयी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संवर्द्धन कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, कला कक्ष, स्मार्ट क्लास, व्यावसायिक शिक्षा कक्ष, अटल टिकरिंग लैब, आई०सी०टी० कक्ष, ईको क्लब बाल संसद, खेल कक्ष, निपुण कक्ष, बाल वाटिका आदि का जायजा लिया।

शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार, ग्रामीण कार्य

मंत्री श्री अशोक चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामकृपाल यादव, पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद श्री संजय कुमार झा, विधान पार्षद श्री ललन सराफ, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उदयकांत, बिहार संग्रहालय के महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० बी० राजेन्द्र, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ० गोपाल सिंह, पटना प्रमण्डल के आयुक्त श्री अनिमेष परासर, जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम०, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेय के० शर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।



मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी (JETA) के शासी निकाय की चतुर्थ बैठक संपन्न



मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी (JETA) के शासी निकाय की चतुर्थ बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जहां-जहां इको टूरिज्म के विकास की बेहतर संभावनाएं हैं उन स्थलों को चिन्हित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने वन, पर्यटन एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि तीनों विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर राज्य में इको टूरिज्म के विकास हेतु बेहतर कार्य योजना बनाते हुए आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक राज्य है। झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के भीतर जिन चिन्हित स्थलों पर इको टूरिज्म विकसित होंगे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा साथ ही प्रकृति की संरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

निर्धारित समयसीमा के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने इको टूरिज्म की संभावनाओं वाले स्थलों का चयन कर वहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाने पर विशेष बल दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने इको टूरिज्म के बढ़ावा एवं विकास को लेकर मैथन, नेतरहाट, पतरातू, चाईबासा, दुमका, रांची सहित कई स्थलों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक में मसानजोर के तर्ज पर पतरातू में भी इको टूरिज्म विकास किए जाने को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इको टूरिज्म विकास की समग्र कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समयसीमा के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

इको टूरिज्म रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि इको-टूरिज्म न केवल राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को राष्ट्रीय एवं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकता है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम भी बन सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों, वन क्षेत्रों, नदियों, जलाशयों और पहाड़ी इलाकों को चिन्हित कर वहां पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए पर्यटन सुविधाओं का विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री श्री सुदिव्य कुमार, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री अबू बकर सिद्दीकी, सचिव, जल संसाधन विभाग श्री प्रशांत कुमार, सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग श्री मुकेश कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं (भस्त्रसूत्र) श्री संजीव कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक श्री एस0आर0 नटेश सहित Ecotourism Society of India के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रांची में बेकन फैक्ट्री के पुनरुद्धार और मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर संपन्न



मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में आज झारखंड विधान सभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, और पशुपालन निदेशालय, कृषि, पशुपालन एवं सहयोग विभाग, झारखंड सरकार के बीच रांची स्थित बेकन फैक्ट्री के पुनरुद्धार और झारखंड में मांस प्रसंस्करण क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए परामर्श सेवाओं हेतु आयोजित एक सहमति पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित यह ऐतिहासिक समझौता झारखंड में पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य की मांस प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एमओयू राज्य सरकार द्वारा संचालित पशुपालन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को मजबूत करने एवं राज्य के पशुधन क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल

साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को मिलेगा बढ़ावा

ICAR-NMRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एम. मुथुकुमार ने कहा कि यह सहयोग आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक प्रथाओं को पेश करके झारखंड के मीट क्षेत्र को बदलने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बेकन फैक्ट्री का पुनरुद्धार राज्य में मांस प्रसंस्करण के क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जिससे किसानों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं सभी को लाभ होगा। ICAR-NMRI के साथ हमारा सहयोग तकनीकी उत्कृष्टता और स्थानीय विकास के बीच एक आदर्श संतुलन है।

MoU के मुख्य उद्देश्य-

रांची में बेकन फैक्ट्री के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए तकनीकी विशेषज्ञता।

झारखंड में व्यापक मांस प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का विकास।

मांस प्रसंस्करण में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का कार्यान्वयन।

मीट क्षेत्र में स्थानीय उद्यमियों और श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण।

मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकी कोर्स हेतु प्रशिक्षण केंद्र की संभावना का निर्धारण।

पूरे राज्य में वैज्ञानिक पशुपालन प्रथाओं को बढ़ावा देना।

इस अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, कृषि सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी, निदेशक पशुपालन श्री आदित्य कुमार आनंद सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

खेतों में बंपर बुवाई, फिर भी एग्रोकेमिकल सेक्टर पर क्यों छाए संकट के बादल?

एक तरफ खेतों में हरियाली है, बुवाई बड़ी है, जलाशय लबालब हैं और फसल की तस्वीर उम्मीद जगाती है, लेकिन दूसरी तरफ एग्रोकेमिकल सेक्टर की हालत उतनी उजली नहीं दिख रही। Nu-vama Institutional Equities की रिपोर्ट एक ऐसी कहानी बयां करती है जहां अच्छी खेती के बावजूद कंपनियों के सामने मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं।

खेत मजबूत, लेकिन बाजार में सुस्ती रबी सीजन ने इस बार उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। गेहूं और तिलहन की बुवाई बड़ी है और कुल रकबा 661 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ऊपर से जलाशयों का स्तर सामान्य से 26 प्रतिशत ज्यादा है, यानी सिंचाई की कोई कमी नहीं। लेकिन इस मजबूत तस्वीर के बावजूद बाजार में एक अजीब ठहराव दिख रहा है। मांग भले बनी हुई है, लेकिन कंपनियों के पास पहले से ही ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है, जो नई बिजली को धीमा कर रहा है।

चौथी तिमाही में फीकी चमक

रिपोर्ट साफ कहती है कि चौथी तिमाही में सेक्टर का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहेगा। कुछ कंपनियां जैसे शारदा क्रॉपकेम बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर घरेलू एग्रोकेमिकल कंपनियों के लिए तस्वीर कमजोर ही दिख रही है। ब्रह्मा प्रदर्शन स्थिर रह सकता है, जबकि धनुका, रैलिस और सुमितोमो जैसी कंपनियां दबाव में रह सकती हैं।

पीआई इंडस्ट्रीज के लिए भी हालात आसान नहीं दिखते।

कीमतों में आग, लेकिन असर बाद में वैश्विक तनाव के कारण कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं और कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। मार्च में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पहले से ज्यादा खरीदारी की, लेकिन इसका फायदा अभी सीमित है। असली असर तब दिखेगा जब कंपनियां नई कीमतों को बाजार में लागू करेंगी, यानी आने वाले महीनों में।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होतीं। चीन में ज्यादा उत्पादन, वैश्विक मांग की कमजोरी और संभावित एल नीनो का खतरा मिलकर सेक्टर पर और दबाव बना सकते हैं। यानी आने वाला समय आसान नहीं है।

खाद कंपनियों के लिए खतरे की घंटी

सबसे ज्यादा चिंता खाद कंपनियों को लेकर है। कच्चे माल की कमी, खासकर सल्फर और अमोनिया की, इनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में सरकार की सब्सिडी नीति पर नजरें टिकी रहेंगी।



ग्रेटर नोएडा की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के साथ जेवर तक नया रास्ता अगले दो माह में तैयार हो जाएगा। यीडा सिटी की साठ मीटर चौड़ी सड़क का साबौता गांव तक विस्तार किया जाएगा। इससे यह सड़क जेवर से भी जुड़ जाएगी।

यमुना एक्सप्रेसवे के विकल्प के तौर पर यह सड़क लोगों की आवाजाही आसान करेगी। एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम होगा। इस पर लोगों को टोल टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही यीडा इस साल में सड़कों के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

यमुना प्राधिकरण की साठ मीटर चौड़ी सड़क ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी देती है। ग्रेटर नोएडा को नोएडा एयरपोर्ट तक सड़क की लंबाई 32 किमी है। यीडा में इसकी लंबाई तकरीबन 25 किमी है। जेवर तक यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर एक और कनेक्टिविटी देने के लिए प्राधिकरण इस सड़क का साबौता तक विस्तार करेगा। इसके लिए तीन किमी सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। दनकौर में जमीनी विवाद निपटने के बाद काम शुरू हो गया है। रुस्तमपुर में सड़क पर डामरीकरण शेष है जबकि दयानतपुर में किसानों के साथ जमीनी विवाद हल होने के बाद निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यमुना एक्सप्रेसवे के विकल्प के तौर पर यह सड़क लोगों की आवाजाही आसान करेगी। एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम होगा। इस पर लोगों को टोल टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही यीडा इस साल में सड़कों के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

प्राधिकरण सड़क के अधूरे हिस्से को जल्द पूरा कर ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी शुरू करेगा। जेवर के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त एक और मार्ग तैयार हो जाएगा।

सड़कों के निर्माण पर 300 करोड़ होंगे खर्च
एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ यीडा सिटी की सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसके

ग्रेटर नोएडा से जेवर तक बनेगा नया रास्ता, एयरपोर्ट को मिलेगी नई कनेक्टिविटी



लिए 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रविधान किया है। इस रकम से विकसित सेक्टरों में अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा किया जाएगा। जिससे यीडा के सेक्टरों व शहर में आवाजाही आसान हो जाएगी।

यीडा अभी तक 3113 औद्योगिक भूखंड आवंटित कर चुका है। 33 फैक्ट्री क्रियाशील होने के अलावा इस साल के अंत तक सौ से अधिक इकाइयां और क्रियाशील हो जाएंगे। इसमें मुख्य तौर पर सेक्टर 32, 33 में टाय पार्क, अपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क के अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क आदि शामिल हैं।

सेक्टर में जमीनी विवाद के कारण कुछ सड़कों का निर्माण अधूरा है। प्राधिकरण जमीनी विवाद को निपटाकर इन सड़कों को पूरा करने में जुटा है। इससे फैक्ट्री में तैयार माल की आवाजाही आसान होगी। साथ ही आवासीय सेक्टर में बसावट होने से वहां रहने वालों को भी आने जाने में सुविधा होगी।

आवासीय सेक्टरों में अधूरी सड़कों को पूरा करेगा यीडा

सेक्टर 18 व 20, 22 डी आवासीय सेक्टर में सड़कों का अभी भी पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया है। जगह-जगह सड़कें अधूरी हैं, जहां बन चुकी है वहां वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जर्जर हो चुकी हैं। 120 मीटर चौड़ी सड़क और सेक्टर 22 डी में आवंटित किए गए फ्लैट तक पहुंचने अभी भी सड़कों का पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया है। जबकि आवासीय सेक्टर में एक हजार से अधिक लोग निर्माण कर कंप्लेशन ले चुके हैं।

सेक्टर 22 डी में रहने वालों को अभी भी बहूखेड़ा गांव से होकर जाना पड़ता है। सड़क समेत अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण लोग अपने फ्लैट में रहने को तैयार नहीं हैं। प्राधिकरण सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि साठ मीटर चौड़ी सड़क का साबौता तक विस्तार किया जाएगा। इससे जेवर तक आवाजाही आसान हो जाएगी। सड़कों के निर्माण पर यीडा चालू वित्त वर्ष में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च करेगा।



उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिमर पाइप्स दशकों तक बिना खराब हुए चल सकते हैं। इनमें स्केलिंग, जंग और रासायनिक नुकसान का प्रभाव कम होता है, जिससे मेंटेनेंस की जरूरत भी कम पड़ती है।

हल्के और आसान इंस्टॉलेशन प्लास्टिक पाइप्स मेटल पाइप्स की तुलना में हल्के होते हैं, जिससे उन्हें ट्रांसपोर्ट, हैंडल और इंस्टॉल करना आसान होता है।

स्मार्ट सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों बढ़ी उत्कर्ष CPVC और UPVC पाइप्स की मांग

भारत में निर्माण क्षेत्र के विस्तार से **CPVC** और **UPVC** पाइप्स की मांग बढ़ी है। शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश तेजी से बढ़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत का पाइप और फिटिंग्स बाजार 2025 में करीब **USD 3.1** मिलियन तक पहुंच गया। 2034 तक करीब **USD 5.6** मिलियन तक बढ़ने की संभावना है।

भारत का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेजी से बदल रहा है। स्मार्ट सिटीज, किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और बड़े स्तर के शहरी जल आपूर्ति सिस्टम-इन सभी में अब हाई-परफॉर्मेंस पाइपिंग सिस्टम की आवश्यकता बढ़ गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में, **CPVC** और **UPVC** पाइप्स बिल्डर्स, डेवलपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर्स की पहली पसंद बनकर उभरे हैं।

पॉलिमर पाइपिंग सिस्टम की ओर यह बदलाव सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं है, बल्कि यह टिकाऊपन, जंग-प्रतिरोध और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन की जरूरत का परिणाम भी है। एक विश्वसनीय पाइप निर्माता के रूप में, उत्कर्ष पाइप्स एंड फिटिंग्सने खुद को उन बिल्डर्स के लिए भरोसेमंद साझेदार के

रूप में स्थापित किया है, जो लंबे समय तक चलने वाले प्लंबिंग और ड्रेनेज सिस्टम की तलाश में हैं।

हाल के सालों में भारत का पाइप और फिटिंग्स सेक्टर तेजी से विकसित हुआ है। इसका मुख्य कारण शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और बढ़ती हाउसिंग डिमांड है। अनुमान के अनुसार, भारत का पाइप और फिटिंग्स बाजार 2025 में लगभग **USD 3.1** मिलियन तक पहुंच गया और 2034 तक लगभग **USD 5.6** मिलियन तक बढ़ने की संभावना है।

प्लास्टिक पाइप उद्योग में भी तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि पारंपरिक मेटल पाइप्स की जगह अब पॉलिमर विकल्प ले रहे हैं। उद्योग रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय प्लास्टिक पाइप बाजार पिछले कुछ वर्षों में लगभग **10.3% CAGR** से बढ़ा है, जिसमें निर्माण, सिंचाई और जल आपूर्ति परियोजनाओं का बड़ा योगदान है।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं—जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और प्रधानमंत्री आवास योजना - भी इस मांग को और बढ़ा रही हैं, क्योंकि इन योजनाओं के तहत लाखों घरों और शहरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी कारणों से

SMART CITY



रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में **CPVC** और **UPVC** पाइप्स का उपयोग तेजी से बढ़ा है।

बिल्डर्स मेटल पाइप्स से पॉलिमर पाइप्स की ओर क्यों बढ़ रहे

निर्माण उद्योग धीरे-धीरे पारंपरिक **GI** और मेटल पाइप्स से हटकर **CPVC** और **UPVC** पाइप्स की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे कई तकनीकी फायदे हैं-

1. जंग-प्रतिरोध

मेटल पाइप्स के विपरीत, **CPVC** और **UPVC** पाइप्स जंग और रासायनिक क्षरण से सुरक्षित रहते हैं। यह उन्हें जल आपूर्ति, इंडस्ट्रियल फ्लूइड ट्रांसफर और ड्रेनेज सिस्टम के लिए आदर्श बनाता है।

2. लंबी आयु

उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिमर पाइप्स दशकों तक बिना खराब हुए चल सकते हैं। इनमें स्केलिंग, जंग और रासायनिक नुकसान का प्रभाव कम होता है, जिससे मेंटेनेंस की जरूरत भी कम पड़ती है।

3. हल्के और आसान इंस्टॉलेशन प्लास्टिक पाइप्स मेटल पाइप्स की तुलना में हल्के होते हैं, जिससे उन्हें ट्रांसपोर्ट, हैंडल और इंस्टॉल करना आसान होता है।

4. तापमान और दबाव सहनशीलता **CPVC** पाइप्स खासतौर पर गर्म और ठंडे पानी के सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। ये उच्च तापमान और दबाव को सहन करने में सक्षम होते हैं।

5. बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किफायती **CPVC** और **UPVC** पाइप्स इंस्टॉलेशन लागत, मेंटेनेंस खर्च और लंबे समय में रिप्लेसमेंट की जरूरत को कम करते हैं, जिससे ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किफायती साबित होते हैं।

आधुनिक निर्माण परियोजनाओं में **CPVC** और **UPVC** पाइप्स का उपयोग

CPVC और **UPVC** पाइप्स की लोकप्रियता उनके बहुउपयोगी अनुप्रयोगों के कारण बढ़ रही है-

1. रेजिडेंशियल प्लंबिंग सिस्टम **CPVC** पाइप्स का उपयोग घरों में गर्म और ठंडे पानी की सप्लाय के लिए किया जाता है, क्योंकि ये थर्मल स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

2. कमर्शियल बिल्डिंग्स होटल, अस्पताल और ऑफिसकॉम्प्लेक्समें **CPVC** पाइप्स का उपयोग स्वच्छ और टिकाऊ जल आपूर्ति के लिए किया जाता

है।

3. ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम **UPVC** पाइप्स अपनी कठोरता, रासायनिक प्रतिरोध और चिकनेस के कारण ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर और जल आपूर्ति परियोजनाएं सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं और नगर निगम परियोजनाओं में लंबे समय तक विश्वसनीयता के लिए पॉलिमर पाइप्स का उपयोग बढ़ रहा है। उद्योग आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल प्लास्टिक पाइप मांग का लगभग 6465व हिस्सा **UPVC** पाइप्स का है, जबकि **CPVC** पाइप्स लगभग 1516व हिस्सेदारी रखते हैं।

बिल्डर्स क्यों चुनते हैं उत्कर्ष पाइपिंग एंड फिटिंग्स जैसे-जैसे विश्वसनीय प्लंबिंग सिस्टम की मांग बढ़ रही है, बिल्डर्स ऐसे निर्माताओं की तलाश में हैं जो गुणवत्ता और प्रदर्शन में निरंतरता प्रदान कर सकें। उत्कर्ष पाइपिंग एंड फिटिंग्स इस क्षेत्र में एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरा है।

उन्नत मैनुफैक्चरिंग विशेषज्ञता

उत्कर्ष उन्नत मैनुफैक्चरिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, जिससे सटीकता, गुणवत्ता और उद्योग मानकों का पालन सुनिश्चित होता है। व्यापक उत्पाद रेंज कंपनी **CPVC** और **UPVC** पाइप्स और फिटिंग्स की विस्तृत रेंज प्रदान करती है, जो जल आपूर्ति, ड्रेनेज और प्लंबिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है।

लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन

उत्कर्ष पाइपिंग सिस्टम्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे दबाव, तापमान और पर्यावरणीय बदलावों को सहन कर सकें।

बिल्डर्स के लिए भरोसेमंद साथी

बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और डेवलपर्स उत्कर्ष पर न सिर्फ उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बल्कि सप्लाय और तकनीकी सहयोग के लिए भी भरोसा करते हैं।

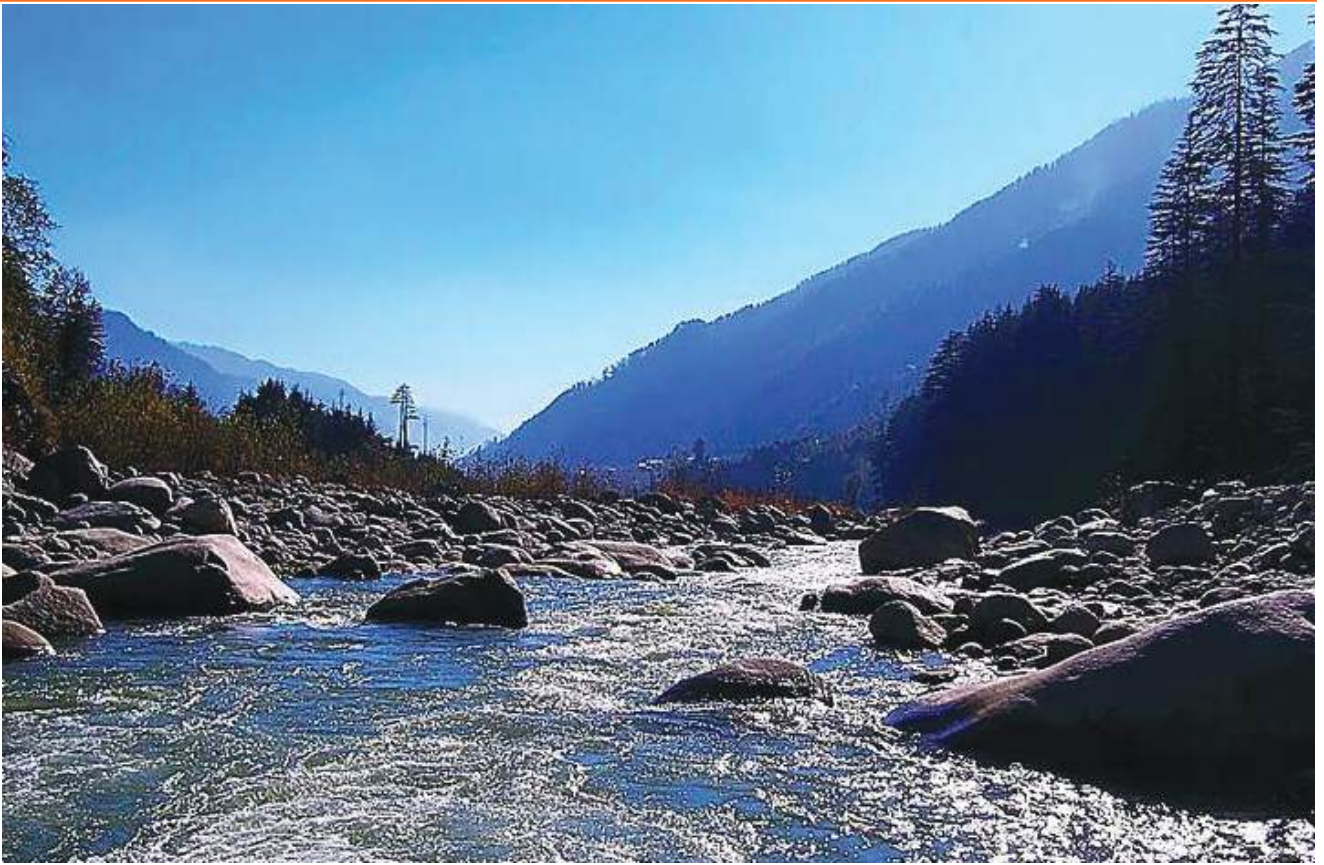
मजबूत मार्केट उपस्थिति

वर्षों के अनुभव के साथ, उत्कर्ष ने खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित किया है।

भारत में पॉलिमर पाइप्स का भविष्य

भारत में **CPVC** और **UPVC** पाइप्स का भविष्य काफी उज्ज्वल है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और जल आपूर्ति व स्वच्छता पर सरकारी फोकस इस मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे।

अनुमान है कि भारत का **PVC** पाइप बाजार 2025 में 3.1 मिलियन टन से बढ़कर 2034 तक 5.6 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द्वारा संचालित होगा। जैसे-जैसे बिल्डर्स टिकाऊपन, स्थिरता और लागत-प्रभावशीलता को प्राथमिकता देंगे, पॉलिमर पाइपिंग सिस्टम भारत के निर्माण इकोसिस्टम का मुख्य हिस्सा बने रहेंगे।



अब ब्यास नहीं मचाएगी तबाही, ड्रेजिंग से होगा रास्ता साफ, भवन निर्माण के लोगों को मिलेगी रेत-बजरी

बरसात का सीजन शुरू होने से पहले नदी की सफाई और तटीकरण करवाने की कोशिश है. अप्रैल-मई महीने में टेंडर अवॉर्ड करने का लक्ष्य है.

कुल्लू- ब्यास नदी से पहली बार उत्तराखंड की ड्रेजिंग पॉलिसी के आधार पर मलबा हटाया जाएगा. हिमाचल में इसकी शुरुआत कुल्लू जिले से की जा रही है. कुल्लू में इस योजना के सफल रहने पर इसे आने वाले समय में प्रदेशभर में लागू किया जा सकता है.

ड्रेजिंग पॉलिसी के सफल रहने पर इससे जहां लोगों को निर्माण सामग्री उपलब्ध होगी, तो वहीं बाढ़ का खतरा भी कम होगा. ड्रेजिंग पॉलिसी के अनुसार नदी के बीच से निकाला जाने वाला मलबा और पत्थर क्रशर में जाएगा. इससे लोगों को भवन निर्माण के लिए बजरी, रेत और अन्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी. इससे जिले में रेत और बजरी की कमी भी नहीं खलेगी. इससे अवैध खनन भी रुकेगा, क्योंकि नदी से मलबा निकालने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाएगी.

बाढ़ के खतरे में आएगी कमी

इस सभी साइटों से संबंधित एफसीए को पहले चरण की स्वीकृति मिल चुकी है और अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है. ब्यास नदी में ड्रेजिंग से निर्माण कार्यों

के लिए सामग्री उपलब्ध होगी. वहीं नदी में जमा मलबा हटने से जल प्रवाह सुचारु होगा और बाढ़ के खतरे में कमी आएगी. इससे आपदा में लोगों के जान माल पर आने वाला संकट टल जाएगा.

कुल्लू से भुंतर तक ब्यास नदी में तीन साइटों को एफसीए की प्रथम चरण की मंजूरी मिल चुकी है और अंतिम मंजूरी बाकी है, उसके बाद इन्हें नीलाम कर कार्य आरंभ किया जा सकेगा.-कान्हा राम, मंडलीय प्रबंधक, वन निगम कुल्लू.

लोगों को मिलेगा सुरक्षा कवच

कुल्लू प्रशासन की योजना है कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले नदी की सफाई और तटीकरण का काम रफ्तार पकड़ ले. इसके लिए अप्रैल और मई महीने में टेंडर अवॉर्ड करने का लक्ष्य रखा गया है. खास बात ये है कि इस बार 'डिजास्टर एक्ट' के तहत प्रारूप तैयार किया गया है, ताकि कानूनी अड़चनों के बिना तेजी से काम हो सके. ऐसे में ड्रेजिंग के कार्य से भुंतर एयरपोर्ट और नदी किनारे लगते घरों को भी सुरक्षा

नदियों की गहराई बढ़ने से बाढ़ के खतरे में कमी.

सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पानी का बेहतर भंडारण.

रेत और खनिज की उपलब्धता से निर्माण कार्यों में आसानी और सरकारी आय में वृद्धि.

ड्रेजिंग के माध्यम से बड़ी-बड़ी मशीन नदी में उतारी जाती है और नदियों में पड़ा हुआ मलबा हटाया जाता है. ड्रेजिंग के माध्यम से नदियों के बहाव को सीधा किया जाता है और मलबे को हटाकर उसकी गहराई बढ़ाई जाती है, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति में पानी नदी के रास्ते होकर गुजरे और आसपास के इलाके को नुकसान न पहुंच सके.



कवच मिलेगा. गौर रहे कि साल 2023 और 2025 की ब्यास नदी की बाढ़ ने भुंतर एयरपोर्ट के रनवे और आसपास की जमीनों को काफी नुकसान पहुंचाया था. ऐसे में अब ब्यास नदी में ड्रेजिंग होने से नदी की गहराई बढ़ेगी और पानी का बहाव सीधा होगा. इससे न केवल एयरपोर्ट सुरक्षित होगा, बल्कि आसपास के लोगों के मकान, खेती वाली जमीन, बगीचे और सरकारी संपत्तियों को भी डूबने से बचाया जा सकेगा. रिवर चैनेलाइजेशन के जरिए पानी के बहाव को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने की कोशिश की जाएगी. **रास्ते में अवसाद जमा करती हैं नदियां**

हिमाचल में सभी नदियां हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं. पहाड़ों और जंगलों से गुजरने के दौरान अपरदन और भूमि कटाव करती हुई अपने साथ कई तरह के अवसाद लाती हैं. इन अवसादों में रेत, सिल्ट, मिट्टी, पत्थर, बोल्टर, लकड़ी मलबे के तौर पर लाती हैं और अपने बेसिन में जमा करती जाती हैं, इससे नदी का तल ऊपर उठा जाता है और मलबा नदी का रास्ता बंद कर देता है इससे नदी का पानी अनियंत्रित होकर आस पास के रिहायशी इलाकों में घुस जाता है और तबाही का कारण बनता है.

ब्यास कई बार मचा चुकी है तबाही

कुल्लू में पहने वाली ब्यास ने तीन दशक में कई बार तबाही मचाई है. वर्ष 1995 में ब्यास ने रौद्र रूप धारण किया था, जिसमें 96 दुकानें, 102 घराट तबाह

हो गए थे, जबकि 19 हजार 300 हेक्टेयर निजी भूमि तहस-नहस हो गई थी. इसके बाद 2005, 2023, 2024 और 2025 में भी बड़े स्तर पर तबाही मचाई. जिला कुल्लू के मनाली के बाहंग से लेकर बजौरा तक ऐसे कई स्थल हैं, जहां ब्यास नदी ने बाढ़ के दौरान बार-बार नुकसान पहुंचाया है. नुकसान की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में बाहंग, भुंतर का सब्जी मंडी इलाका, भुंतर ब्रिज, छरुडू, लुगाड भट्टी आदि शामिल हैं.

तथा है ड्रेजिंग

हिमालयन नीति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि ड्रेजिंग से बाढ़ के खतरे को काम किया जा सकेगा. ड्रेजिंग पॉलिसी मुख्य रूप से नदियों के तल में जमा गंदगी, रेत, गाद और मलबे को मशीन से बाहर निकाला जाता है. इससे नदी का रास्ता खुल जाता है. नदी का प्रवाह सुनिश्चित होता है और मानसून में नदी के बहाव से नुकसान की संभावना कम हो जाती है. इसका प्राथमिक उद्देश्य बाढ़ के खतरे को कम करना और नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाना है, ताकि बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके. विशेषज्ञों के अनुसार, सालों से जमा गाद के कारण नदियों का तल ऊंचा हो गया है, जिससे कम बारिश में भी पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस जाता है. नई नीति के तहत चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर ड्रेजिंग मशीनें लगाकर नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी. कुल मिलाकर नदियों की ड्रेजिंग से बाढ़ और आपदा को टाला जा सकता है.

साथ ही अवैध खनन को रोकने में भी मिलती है. हालांकि ड्रेजिंग शुरू करने से पहले सरकार नदी-नालों की वैज्ञानिक मैपिंग करवाती है, ताकि जलीय जीवन पर असर न पड़े. ड्रेजिंग की आड़ में अनियंत्रित खनन से नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है.

डीसिल्टेशन और इकोलॉजी

एमए चितले की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी ने मई, 2017 में 'भीमगौड़ा (उत्तराखंड) से फरक्का (पश्चिम बंगाल) तक गंगा नदी की डीसिल्टेशन (गाद निकालने के काम) के लिए दिशानिर्देशों की तैयारी' पर अपनी रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को सौंपी थी.

कमेटी ने टिप्पणी की कि नदियों में सिल्टेशन (गाद जमा होना) एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. फिर भी भारी वर्षा, जंगलों के कटान, जलाशयों के जल में संरचनागत हस्तक्षेप और बाढ़ बनाने से नदियों में सिल्टेशन बढ़ता है. इसका नतीजा यह होता है कि नदियों की बहाव क्षमता कम होती है और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है. साथ ही नदियों में जल भंडारण के उपायों को भी नुकसान पहुंचता है, जब नदी को चौड़ा या गहरा किए बिना उसकी प्राकृतिक क्षमता को बरकरार रखने के लिए महीन गाद और तलछट को निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को डीसिल्टेशन कहा जाता है. डीसिल्टेशन से नदी के हाइड्रॉलिक प्रदर्शन में सुधार होता है. फिर भी अंधाधुंध गाद निकालने से नदी की इकोलॉजी और प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

प्रमुख लाभ

नदियों की गहराई बढ़ने से बाढ़ के खतरे में कमी. सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पानी का बेहतर भंडारण. रेत और खनिज की उपलब्धता से निर्माण कार्यों में आसानी और सरकारी आय में वृद्धि. ड्रेजिंग के माध्यम से बड़ी-बड़ी मशीन नदी में उतारी जाती है और नदियों में पड़ा हुआ मलबा हटाया जाता है. ड्रेजिंग के माध्यम से नदियों के बहाव को सीधा किया जाता है और मलबे को हटाकर उसकी गहराई बढ़ाई जाती है, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति में पानी नदी के रास्ते होकर गुजरे और आसपास के इलाके को नुकसान न पहुंच सके.

दिल्ली का द्वारका

बनेगा अंतरराष्ट्रीय केंद्र, आईटी हब और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से बदलेगी तस्वीर

पश्चिमी दिल्ली- उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने द्वारका को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की बड़ी योजना सामने रखी है। आईटी/आईटीईएस हब, पांच सितारा होटल, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर और अत्याधुनिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं के जरिए द्वारका को फ्यूचर रेडी स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा, जो निवेश, रोजगार और शहरी जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाएगा।

द्वारका सब-सिटी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी क्षेत्रों में वैश्विक स्तर की नागरिक सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने द्वारका की रणनीतिक कनेक्टिविटी यूईआर-II, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। उपराज्यपाल ने कहा कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, भारत वंदना पार्क और सेक्टर-24 का गोल्फ कोर्स जैसे प्रोजेक्ट द्वारका को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं।

इसके लिए एक समयबद्ध और समग्र रोडमैप तैयार कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों, दूतावासों और वैश्विक संस्थानों को यहां आयोजन के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान स्टार्म वाटर चैनल नंबर-2 और 5, सेक्टर-23 के पांच सितारा होटल प्रोजेक्ट, सेक्टर-26 में प्रस्तावित आईटी, आईटीईएस हब और सेक्टर-24 स्थित गोल्फ कोर्स का दौरा किया गया। एलजी ने

इन परियोजनाओं की गुणवत्ता, उपयोगिता और आम जनता पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन किया।

स्टार्म वाटर चैनल परियोजनाओं को शहरी बदलाव का माडल बताते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें हरित कारिडोर में बदला गया है, जहां साइकिल ट्रैक, वाकवे, सोलर इंस्टॉलेशन और सामुदायिक सुविधाएं विकसित की गई हैं।

इससे जल निकासी व्यवस्था मजबूत होने के साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सेक्टर-23 में विकसित किए जा रहे पांच सितारा होटल प्रोजेक्ट को स्पेशल लाइसेंस फीस माडल पर तैयार किया जाएगा, जिसमें निजी भागीदारी के तहत 200 से अधिक कमरों की सुविधा होगी।

वहीं, यूईआर-II के पास प्रस्तावित आईटी और आईटीईएस हब से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की

उम्मीद है। दौरे के अंतिम चरण में एलजी ने सेक्टर-24 स्थित गोल्फ कोर्स का निरीक्षण किया, जिसे पे एंड प्ले माडल पर विकसित किया जा रहा है। यह देश के प्रमुख सार्वजनिक गोल्फ सुविधाओं में से एक होगा, जो खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा और युवाओं को अवसर प्रदान करेगा। एलजी ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं का उद्देश्य केवल ढांचागत विस्तार नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, हरित क्षेत्र बढ़ाना और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने डीडीए को शहरी सौंदर्यीकरण, हरित गतिशीलता और मनोरंजन से जुड़े और अधिक लैंडमार्क प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीडीए ने भरोसा जताया कि एलजी के मार्गदर्शन में दिल्ली में योजनाबद्ध, समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास को नई गति मिलेगी।



पक्का घर बनाने का सपना होगा पूरा! सरकार की आवास योजना से सीधा खाते में मिलेगी आर्थिक मदद

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीब और कम आय वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दो हिस्सों में चलती है और 2026 में भी लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत सरकार घर बनाने के लिए आर्थिक मदद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में **PMAY-G** (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) और शहरी क्षेत्रों में **PMAY-U** (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी) चलाई जा रही है। इसमें अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। भारत सरकार अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाती है जिससे लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना (**PMAY**)। जिसका मकसद गरीब और कम आय वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना दो मुख्य हिस्सों में चलती है एक है ग्रामीण (**PMAY-G**) और दूसरी शहरी (**PMAY-U**) है। साल 2026 में भी यह योजना लाखों परिवारों को फायदा पहुंचा रही है।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (**DBT**) के जरिए मिलती है, ताकि कोई बीच में कटौती न हो और पैसा सही समय पर पहुंचे।

ग्रामीण क्षेत्रों में **PMAY-G** (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण)

यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाती है। इसका लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर या कच्चे/जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर मिले, जिसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था होती है। मैदानी इलाकों में हर घर के लिए 1.20 लाख की सहायता मिलती है, जबकि पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाकों (जैसे जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वोत्तर राज्य, लद्दाख) में 1.30 लाख तक मिलती है।

यह राशि तीन या चार किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त निर्माण शुरू होने पर, दूसरी प्लिंथ लेवल पर, तीसरी छत बनने पर और आखिरी किस्त पूरा होने पर। पैसा लाभार्थी के आधार लिंकड बैंक खाते में सीधे आता है। इसके अलावा, **MGNREGA** या अन्य योजनाओं से शौचालय के लिए 12,000 अतिरिक्त मदद मिल सकती है। लाभार्थी 70,000 तक का लोन भी कम ब्याज पर ले सकते हैं। 2026 तक करोड़ों घर बन चुके हैं आने वाले सालों में भी कई निर्माणाधीन हैं।

लाभार्थी चुनने के लिए **स्वच्छ-2011 डेटा और ग्राम सभा** की सत्यापन प्रक्रिया होती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और पात्र हैं, तो **pmayg.nic.in** या अपडेटेड पोर्टल **pmayg.dord.gov.in** पर जाकर नाम चेक कर सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों में **PMAY-U** (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी)

शहरी इलाकों के लिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यह योजना चलाता है। इसका फोकस झुग्गी-झोपड़ी वालों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**), निम्न आय वर्ग (**LIG**) और मध्यम आय वर्ग (**MIG**) पर है। मुख्य फायदा घर खरीदने, बनाने या बढ़ाने पर होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के रूप में मिलता है।

EWS और **LIG** के लिए 6.5% तक ब्याज सब्सिडी, अधिकतम 2.67 लाख तक।

MIG-I (6-12 लाख आय) के लिए 4% सब्सिडी, अधिकतम 2.35 लाख।

MIG-II (12-18 लाख आय) के लिए 3% सब्सिडी, अधिकतम 2.30 लाख।

2024 से **PMAY-U 2.0** शुरू हुई है, जिसमें

लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी पहले 8 लाख तक 12 साल के लिए मिलती है, कुल सब्सिडी 1.80 लाख तक। यह सब्सिडी **NHB** या संबंधित संस्था से 5 साल में किस्तों में मिलती है और लोन अकाउंट में एडजस्ट होती है। **BLC** (व्यक्तिगत निर्माण) के तहत 1.5 लाख सीधे सहायता मिलती है। पैसा **DBT** से बैंक में जाता है। आवेदन बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या **pmaymis.gov.in** पर होता है।

कैसे पाएं आर्थिक मदद?

सबसे पहले पात्रता चेक करें - कोई पक्का घर न हो, आय सीमा में हो, और पहले किसी योजना का फायदा न लिया हो।

ग्रामीण योजना के लिए- ग्राम पंचायत या **ष्ट** से आवेदन।

शहरी के योजना के लिए- बैंक/ऑनलाइन पोर्टल से।

डॉक्यूमेंट्स -आधार, बैंक पासबुक, आय प्रमाण, घर का फोटो आदि यह योजना गरीब परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप पात्र हैं, तो जल्दी आवेदन करें और स्टेट्स चेक करें। लिस्ट में नाम आते ही आपको किस्तें मिलना शुरू हो जाती हैं।



अमेरिका ईरान युद्ध- उत्तराखंड में घर बनाना हुआ मुश्किल, निर्माण सामग्री के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा बजट



मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण निर्माण क्षेत्र लड़खड़ाया, सीमेंट, सरिया, ईट, रेत, बजरी और टाइल्स के दाम बढ़ने से आम आदमी पर पड़ा बोझ

देहरादून से किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट- मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ घरेलू बाजारों में भी साफ रूप से दिखाई देने लगा है। खासतौर पर निर्माण क्षेत्र इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर प्रमुख सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, ईट, रेत, बजरी, टाइल्स और अन्य फिटिंग्स की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी से लोग परेशान हो गए हैं।

कुछ लोगों ने घर बनाना शुरू किया है, तो कुछ अब सोच रहे हैं। लेकिन हर चीज पर बढ़ती महंगाई लोगों के रसोई से लेकर मकान के सामान पर दिखने लगी है। ऐसे लाखों लोग हैं, जो अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं या पहले से निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की लागत में

बढ़ोत्तरी, ईंधन की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन में बाधाओं ने मिलकर इस महंगाई को और तेज कर दिया है। आइये जानते हैं क्या क्या हुआ है बाजार में।

सरिया और सीमेंट के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी से निर्माण लागत में भारी इजाफा- आप अगर कुछ भी निर्माण करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सरिया और सीमेंट। यही दोनों चीजें हाल के दिनों में बेहद महंगे हो गए हैं। युद्ध से पहले जहां सरिया के दाम औसतन 50,000 से 52,000 प्रति टन के बीच थे, वहीं अब यह 60,000 से 65,000 प्रति टन तक पहुंच चुके हैं। ये दाम अलग अलग शहरों के हैं। देहरादून में अभी सरिया के दाम 63,000 टन चल रहे हैं। देहरादून के हर्षावाला स्टेशन के समीप सरिये का कारोबार करने वाले रोबिन अग्रवाल कहते हैं कि-

कुछ स्थानों पर गुणवत्ता और ब्रांड के अनुसार यह कीमत इससे भी ऊपर जा रही है। इसी तरह सीमेंट के दामों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पहले सीमेंट की जो एक बोरी 360 से 380 के बीच मिल जाती थी, वह अब 400 से 410 तक बिक रही है। हालांकि अभी देहरादून में पूरा स्टॉक है, लेकिन नए रेट जल्द लागू हो सकते हैं।

-रोबिन अग्रवाल, सरोया कारोबारी-

रोबिन कहते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किल बढ़ेगी। इस बढ़ोत्तरी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। लोहे और कोयले के आयात की लागत में वृद्धि उत्पादन खर्च में इजाफा और परिवहन महंगा होने के कारण कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। इसका असर ये हो रहा है कि हर इंसान के मकान बनाने की लागत में 15 से 25 प्रतिशत तक का इजाफा होना तय है। ये आम आदमी के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका है।

ईट, रेत और बजरी की कीमतों में उछाल, छोटे शहरों में और ज्यादा असर- सीमेंट और सरिया के अलावा ईट रेत और बजरी जैसी बुनियादी सामग्रियों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। पहले जहां ईट 6 से 7 प्रति पीस मिलती थी, अब इसकी कीमत कई जगह पर 8 से 8 रुपए 50 पैसे तक पहुंच रही है। कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाली ईट 10 तक बिक रही है।

रेत की कीमतों में भी अचानक बढ़ोत्तरी- रेत पहले 90 से 95 प्रति क्विंटल मिल रही थी। इसी कारोबार से जुड़े गोविन्द सिंह कहते हैं कि हमारे यहां फिर भी बहुत पैदावार है, लेकिन अन्य राज्यों में ये कीमत और अधिक हो जाएगी। रेत दूर से आती है, लेकिन फिर भी ये बात

सही है कि महंगाई का असर आम आदमी के सामने घर बनाने में तो पड़ ही रहा है।

टाइल्स, मार्बल और इंटीरियर सामग्री भी हुई महंगी-गैस की कीमतों का असर निर्माण के अंतिम चरण में उपयोग होने वाली टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य इंटीरियर सामग्री में भी दिखाई पड़ रहा है। बाजार में टाइल्स उद्योग में गैस का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण गैस की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते टाइल्स की कीमतों में करीब 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। पहले जहां सामान्य टाइल्स 35 से 40 प्रति वर्ग फुट मिलती थीं, अब वही 45 से 50 और उससे भी अधिक पहुंच गई है।

कुछ लोग पुराना माल होने की वजह से वजह से अभी वही रेट लगा रहे हैं, लेकिन नए आने वाले माल की कीमत में इजाफा हो गया है। प्रीमियम और डिजाइनर टाइल्स के दाम इससे भी अधिक बढ़े हैं। इसके अलावा बाथरूम फिटिंग्स, पाइप, वायरिंग, पेंट और अन्य सजावटी सामग्री की कीमतों में भी 4 से 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे कुल निर्माण लागत और बढ़ गई है।

परिवहन लागत में उछाल ने बढ़ाया बोझ, डीजल महंगा होने से असर गहरा- बाजार पर नजर रखने वाले साहिब सिंह कहते हैं कि-

निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण परिवहन लागत में वृद्धि भी है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ट्रकों और अन्य वाहनों से सामग्री ढुलाई महंगी हो गई है।

उत्तर भारत के कई शहरों जैसे हरिद्वार, देहरादून और पहाड़ी शहर ही नहीं यूपी बिहार जैसे शहरों में भी परिवहन शुल्क में 30 से 50 तक प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। इससे दुकानदारों और ठेकेदारों को अधिक कीमत पर सामग्री खरीदनी पड़ रही है। इसका भार आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ता है। ईंधन की कीमतों में अस्थिरता के चलते आने वाले समय में यह लागत और बढ़ सकती है।

-साहिब सिंह, बाजार विशेषज्ञ-

सप्लाई चेन पर असर, आयातित कच्चे माल की कमी से उत्पादन प्रभावित- साहिब सिंह का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ा है। कई देशों से आने वाले कच्चे माल जैसे कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद और धातुओं

की सप्लाई बाधित हुई है। इससे निर्माण सामग्री बनाने वाली कंपनियों को उत्पादन में कठिनाई हो रही है और लागत बढ़ रही है। कई फैक्ट्रियां अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पा रही हैं, जिससे बाजार में उपलब्धता कम हो रही है और कीमतें ऊपर जा रही हैं।

आम आदमी पर सीधा असर, घर बनाने का सपना होता जा रहा महंगा- देहरादून में मकान बनाने की सोच रहे सुभाष रमोला अभी मकान बनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो अभी युद्ध की वजह से महंगी हुई चीजों को देख कर शांत बैठे हैं। सुभाष सभी चीजें सामान्य होने का इन्तजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि- जो अपनी बचत और कर्ज के सहारे घर बनाने की योजना बना रहा था, अभी वो टालने की सोच रहा हूँ।

यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। देहरादून शहर में जहां पहले एक सामान्य 1000 वर्ग फुट का मकान 15 से 18 लाख में तैयार हो जाता था, अब उसी मकान की लागत 22 से 25 लाख तक पहुंच रही है। इससे कई लोग अपने निर्माण कार्य को बीच में ही रोकने या भविष्य के लिए टालने को मजबूर हो गए हैं।-सुभाष रमोला, देहरादून निवासी-



एग्रीस्टैक बनेगा 'अगला UPI'?

किसानों के लिए डिजिटल क्रांति

इसका इरादा 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल आईडी तैयार करना और किसान पंजीकरण, भू अभिलेख और फसल डेटा को जोड़ने वाले तीन बुनियादी डेटाबेस तैयार करना है

इस सप्ताह आयोजित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही डिजिटल अधोसंरचना 'एग्रीस्टैक' को भावनात्मक रूप से 'अगला यूपीआई' करार दिया। वह उस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का हवाला दे रही थीं जिसने न केवल देश में खुदरा भुगतान प्रणाली को क्रांतिकारी ढंग से बदल दिया बल्कि अब उसका विदेश में भी विस्तार हो रहा है।

परंतु यूपीआई की अवधारणा अपेक्षाकृत सरल है। यह उपयोगकर्ता के बैंक खातों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ता है और गूगल पे या फोनपे जैसे वाणिज्यिक ऐप के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है। इसके विपरीत एग्रीस्टैक कहीं अधिक महत्वाकांक्षी और जटिल प्रयास है जो केंद्र एवं राज्यों की प्रशासनिक तथा आईटी क्षमताओं की परीक्षा लेगा।

इसका इरादा 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल आईडी तैयार करना और किसान पंजीकरण, भू अभिलेख और फसल डेटा को जोड़ने वाले तीन बुनियादी डेटाबेस तैयार करना है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है- किसानों को न्यूनतम कागजी कार्रवाई या सेवा प्रदाताओं के पास जाने की जरूरत के बिना लाभ और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।

केंद्र द्वारा सितंबर 2024 में अनुमोदित इस परियोजना के तहत राज्यों को अपने किसानों का पंजीकरण करने के लिए वित्तीय मदद आवंटित की गई है। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब तक 8.62 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। केंद्र का लक्ष्य मार्च 2027 तक इस कार्य को पूरा करना है। इसलिए एग्रीस्टैक को प्रभावी बनाने के लिए बारीक डेटा संग्रह आवश्यक है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में ड्रेन तकनीक का उपयोग करके कृषि भूमि की डिजिटल मैपिंग में तेजी से प्रगति हुई है किंतु भू-स्वामित्व स्थापित करना एक कठिन काम रहा है।

सैद्धांतिक तौर पर ऐसा इसलिए क्योंकि देश के करीब 20 फीसदी किसान परिवार जमीन पट्टे या बंटाई पर लेकर खेती करते हैं जबकि जमीन के वास्तविक स्वामी बड़े शहरों या विदेशों में बस चुके हैं।



कुछ राज्यों में बंटाई या पट्टे पर खेती करने वालों का अनुपात 36 फीसदी तक है। इसके बावजूद अगर किसानों का पंजीयन और भू-अभिलेख को सही तरीके से दर्ज किया जाता है तो एग्रीस्टैक एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है।

खासतौर पर भूमिहीन खेतिहर किसानों के लिए जो बंटाई या पट्टे पर खेती करने वाले किसानों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं और छोटे जोत और सीमित स्वायत्तता के कारण सबसे अधिक असुरक्षित वर्ग में आते हैं। इनमें से अधिकांश की संस्थागत ऋण या फसल बीमा जैसी सरकारी सहायता योजनाओं या पीएम किसान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम तक बहुत कम पहुंच है। इसके तहत न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि उर्वरक का 60 फीसदी उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके नाम पर जमीन नहीं है। दरअसल, उर्वरकों के उपयोग में एग्रीस्टैक महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह आगामी वित्तीय वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट वाली बढ़ती सब्सिडी को नियंत्रित करने और मिट्टी की सेहत को बहाल करने, दोनों में कारगर साबित हो सकता

है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में एग्रीस्टैक का उपयोग करके भूमि, उर्वरक उपयोग और उगाई गई फसलों को जोड़ने वाले एक प्रयोग से भारी बचत हुई।

सबसे बड़ी कटौती यूरिया में हुई, जिस पर इतनी अधिक सब्सिडी दी जाती रही है कि इसके लगातार अत्यधिक उपयोग से उर्वरक उपयोग में असंतुलन पैदा हो गया है। वर्षों से, फॉस्फेटिक (पी) और पोटैशियम (के) उर्वरकों की तुलना में यूरिया (एन) का यह अत्यधिक उपयोग, जिसे आमतौर पर एनपीके असंतुलन के रूप में जाना जाता है, मिट्टी के क्षरण और कृषि उत्पादकता में गिरावट का एक प्रमुख कारण रहा है।

इसलिए, एग्रीस्टैक उर्वरक सब्सिडी के वितरण में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव ला सकता है, जिससे सब्सिडी निर्माताओं के बजाय सीधे किसानों तक पहुंचेगी। प्रत्यक्ष हस्तांतरण से उपयोग में पारदर्शिता भी आ सकती है, जिससे सब्सिडी का अधिक सटीक समायोजन संभव हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लगभग 30,000-40,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

लेकिन बहुत कुछ डेटा संग्रह तंत्र की सटीकता और दक्षता पर भी निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र में किसानों के लिए तीसरी ऋण माफी योजना, राजकोषीय जोखिम और नैतिक चुनौती

इस योजना के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों के फसल ऋण बकाया हैं, उनके अधिकतम 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह, राज्य विधान सभा में बजट पेश करते समय अपने एक चुनावी वादे को पूरा किया। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में सरकार की सराहना की जाती है लेकिन इस बार मामला थोड़ा जटिल है। यह वादा किसानों के कृषि ऋण माफी से जुड़ा है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना के नाम से शुरू की जा रही योजना राज्य के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। दरअसल पिछले दस वर्षों में महाराष्ट्र की सरकारों, किसानों के लिए यह तीसरी ऋण माफी योजना ला रही हैं।

इस योजना के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों के फसल ऋण बकाया हैं, उनके अधिकतम 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। इसके अलावा जो किसान नियमित रूप से अपने ऋण की किस्तें चुकाते रहे हैं, उन्हें भी अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र का ऋण, उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का लगभग 19 फीसदी है जो राष्ट्रीय औसत से कम है ऐसे में राज्य को इस तरह के लोकलुभावन कदमों से बचना चाहिए। राज्य में महिलाओं के लिए नकद राशि का वितरण करने की एक लोकप्रिय योजना भी पहले से चल रही है। भारत में कृषि ऋण माफी का लंबा इतिहास रहा है। ऐसी योजनाएं सरकार के राजकोषीय संतुलन को काफी हद तक बिगाड़ देती हैं लेकिन लंबे समय में कृषि क्षेत्र की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं कर पातीं। इसके अलावा इसके कारण नैतिक जोखिम वाली समस्या भी होती है।

जब किसानों या किसी अन्य समूह को यह उम्मीद होने लगे कि वे सरकार पर दबाव बनाकर ऋण माफी हासिल कर सकते हैं तो उनमें समय पर ऋण चुकाने को लेकर दबाव कम हो जाता है। इस बार राज्य सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए उन किसानों को भी भुगतान देने की बात कही है जिन्होंने नियमित रूप से अपने ऋण चुकाए हैं। लेकिन जब तक ऐसे किसानों को उनकी चुकाई गई पूरी राशि वापस नहीं मिलती तब तक यह समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी।

इसके अलावा इससे ऋण माफी की दूसरी बड़ी समस्या और बढ़ जाती है, यानी सरकारी खजाने पर

पड़ने वाला भारी बोझ। महाराष्ट्र के अपने इतिहास से भी अंदाजा मिलता है कि सवाल सिर्फ व्यक्तिगत स्तर के नैतिक जोखिम का नहीं है बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र में ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें कर्ज लेकर विस्तार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है क्योंकि यह मान लिया जाता है कि भविष्य में सरकार किसी न किसी रूप में सहायता देकर जोखिम अपने ऊपर ले लेगी। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह भी संभव है कि ऐसी मांगें अन्य राज्यों में भी उठने लगें।

देश के बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस समस्या को लेकर पहले ही चेतावनी दी है। उसका कहना है कि राजनीतिक चक्र में बार-बार की जाने वाली कृषि ऋण माफी योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में ऋण की संस्कृति को कमजोर कर दिया है। दरअसल, इसका असर उसी वर्ग पर पड़ता है जिसकी मदद करने का दावा सरकार करती है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान किसानों को कर्ज देने में हिचकिचाने लगते हैं क्योंकि उन्हें यह आशंका रहती है कि किसान ऋण चुकाने के बजाय कर्ज में चूक कर सकते हैं। इस तरह आखिरकार किसानों तक ऋण के प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आरबीआई ने इन ऋण माफी योजनाओं के राजनीतिक संबंध को

भी स्पष्ट किया था। आरबीआई ने 2019 में बताया कि पिछले पांच वर्षों में घोषित 10 कृषि ऋण माफी योजनाओं में से आठ योजनाएं, चुनाव से 90 दिनों के भीतर घोषित की गई थीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी योजनाओं का लाभ आखिरकार सबसे कमजोर किसानों को नहीं मिल पाता है। अधिक से अधिक ये योजनाएं, पात्र लाभार्थियों के लगभग आधे हिस्से तक ही पहुंचती हैं और अक्सर इससे भी कम लोगों को लाभ मिलता है। इनमें भी आमतौर पर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले किसान ही लाभान्वित होते हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि ऐसी कृषि सुधार नीतियां, जिनसे किसानों को सीधे आमदनी से जुड़ी सहायता मिल सके, उन्हें अभी तक गंभीरता से क्यों नहीं लागू किया गया।

जब तक केंद्र सरकार के स्तर पर कृषि सब्सिडी की व्यवस्था में विकृतियां बनी रहेंगी तब तक राज्यों की राजनीति ऐसे ही वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदार कदमों के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी। इसके अलावा यह सवाल पूछना लाजिमी है कि यदि पिछली ऋण माफी योजनाएं, कृषि क्षेत्र की मूल संरचनात्मक समस्याओं का हल नहीं निकाल सकीं तब नई योजना इन समस्याओं को किस हद तक सुलझा पाएगी।



‘भव्य’ योजना से मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कवायद

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 33,660 करोड़ रुपये की स्कीम भव्य (भारत औद्योगिक विकास योजना) को मंजूरी दी है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 33,660 करोड़ रुपये की स्कीम ‘भव्य’ (भारत औद्योगिक विकास योजना) को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 प्लग-एंड-प्ले यानी इस्तेमाल के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जानी है। यह देश के विनिर्माण आधार को मजबूती देने, रोजगार निर्माण को बढ़ावा देने और कारोबारी सुगमता में सुधार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। ये पार्क 33,000 एकड़ में फैले होंगे और इन्हें छह साल में तैयार किया जाएगा।

ये उद्यमों के लिए पूर्व मंजूरी वाली जमीन, तैयार अधोसंरचना और एकीकृत सेवाएं मुहैया कराएंगे। इसके लिए राज्यों की ओर से मजबूत एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली और नियमन में ढील जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। मूल बुनियादी ढांचे मसलन आंतरिक संपर्क के लिए सड़कों, अंडरग्राउंड सुविधाओं, नाली और साझा सुविधाओं आदि के लिए एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनुमान बताते हैं कि इससे करीब 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार तैयार हो सकते हैं और क्लस्टर आधारित विकास के जरिये घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है।

धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, विक्रम उद्योगपुरी और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्र जैसे मौजूदा औद्योगिक केंद्र ‘प्लग-एंड-प्ले’ इकोसिस्टम की संभावनाओं को अच्छी तरह से दर्शाते हैं, जहां पूर्व-स्वीकृत भूमि, एकीकृत बुनियादी ढांचा और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी तेज औद्योगिकीकरण को संभव बनाते हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम, जो वर्तमान में 13 राज्यों में 20 परियोजनाओं को लागू कर रहा है, उसने दिखाया है कि ऐसे मॉडल प्रवेश बाधाओं को कम करके और परियोजना की तत्परता में सुधार करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ बड़े व्यवसायों को भी आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि निर्माण में देरी और कार्य पूरा करने के लिए



लंबी समयसीमा जैसी चुनौतियां अक्सर लागत बढ़ा देती हैं और निवेशकों के विश्वास को कमजोर करती हैं। अतीत के अनुभवों में चेतावनी देने वाला सबक भी छिपा है। विभिन्न राज्यों में कई औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका। उदाहरण के लिए कर्नाटक के कुछ पार्कों में कुल आवंटित इकाइयों की केवल 25 फीसदी ही संचालित हैं। इसकी वजह खराब कनेक्टिविटी, कमजोर संचालन नियामकीय ढेरी और मांग की कमी आदि हैं। इसी प्रकार कई विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक कॉरिडोर विभिन्न दिक्कतों से जूझते रहे हैं।

आंतरिक बुनियादी ढांचे को बाहरी नेटवर्क जैसे राजमार्गों, रेल मालवाहक कॉरिडोर और बंदरगाहों के साथ समन्वित करने में देरी अक्सर औद्योगिक पार्कों के परिचालन को बाधित कर देती है। भूमि और बुनियादी सुविधाएं तैयार होने पर भी कंपनियों को बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी तक भरोसेमंद तरीके से पहुंचने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जिससे परिचालन लागत बढ़ती है और प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आती है। यह दर्शाता है कि ‘कारोबारी सुगमता’ केवल

नीति निर्माण का विषय नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर निरंतर क्रियान्वयन और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का भी है। सफल होने के लिए, भव्य को क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। योजना का जोर पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकरण के माध्यम से निर्बाध रूप से ‘अंतिम सिरे तक संपर्क’ सुनिश्चित करने पर है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। विश्वसनीय बिजली, पानी और डिजिटल ढांचा जिन्हें भूमिगत यूटिलिटी कॉरिडोर जैसी सुविधाओं का समर्थन प्राप्त हो निरंतर औद्योगिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए गारंटीशुदा होना चाहिए।

योजना की ‘चुनौती-आधारित चयन प्रक्रिया’ के तहत उच्च गुणवत्ता वाली, निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों को प्राथमिकता देनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, औषधि और पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टरिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इन पार्कों को कौशल विकास इकोसिस्टम से जोड़ना भी आवश्यक है ताकि रोजगार सृजन समावेशी और टिकाऊ हो।

बकरी पालन पर मिल रही 90% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का पूरा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी पहल करते हुए बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यदि कोई किसान या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति बकरी पालन का छोटा यूनिट स्थापित करता है, तो उसे सरकार की ओर से 90% तक सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

दरअसल, बकरी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें जोखिम भी अपेक्षाकृत कम होता है। यही वजह है कि सरकार इस सेक्टर को तेजी से बढ़ावा दे रही है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से इससे जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकें।

पहले मिलती थी 50% सब्सिडी, अब 90% तक लाभ

पशुपालन विभाग द्वारा पहले बकरी पालन के लिए दो प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही थीं। पहली योजना में 100 बकरी और 20 बकरों की यूनिट लगाने पर 50% तक सब्सिडी दी जाती थी। वहीं, दूसरी योजना के तहत 10 बकरी और 2 बकरों की यूनिट पर भी 50% अनुदान मिलता था। अब सरकार ने इस योजना को और अधिक लाभकारी बनाते हुए छोटे यूनिट्स पर सब्सिडी बढ़ाकर 90% तक कर दी है। इससे गरीब और छोटे किसानों के लिए इस व्यवसाय को शुरू करना काफी आसान हो गया है।

कमजोर वर्गों को मिलेगी प्राथमिकता

इस योजना में समाज के वंचित वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप





से कमजोर वर्ग (EWS) और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। खासतौर पर महिलाओं को इस योजना से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वे घर बैठे ही आय का साधन विकसित कर सकें।

इस योजना की खास बात यह है कि सरकार केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि लाभार्थियों को बकरी पालन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को बकरियों की देखभाल, पोषण, बीमारियों से बचाव और मार्केटिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी। इससे किसान इस व्यवसाय को बेहतर तरीके से चला सकेंगे और उन्हें नुकसान होने की संभावना भी कम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना प्रशिक्षण के पशुपालन शुरू करने पर कई बार किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इस योजना में ट्रेनिंग शामिल होने से सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही एक पारंपरिक व्यवसाय रहा है, लेकिन अब इसे आधुनिक तरीके से विकसित किया जा रहा है। सरकार की यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि गांवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इसके अलावा इस तरह की योजनाएं ग्रामीण पलायन को रोकने में भी अहम भूमिका निभा सकती

हैं, क्योंकि लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिलने लगेगा।

किसानों के लिए सुनहरा अवसर

कुल मिलाकर, बकरी पालन पर 90व तक सब्सिडी देने की यह योजना किसानों और कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा अवसर है। कम लागत में व्यवसाय शुरू करने, सरकारी सहायता और प्रशिक्षण के साथ यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। जो किसान या ग्रामीण इस क्षेत्र में काम करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय के नए स्रोत तैयार करें।

बकरी पालन सब्सिडी के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

प्रश्न 1. बकरी पालन योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

उत्तर- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बकरी पालन यूनिट स्थापित करने पर 90% तक सब्सिडी दी जाती है।

प्रश्न 2. इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?

उत्तर- इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।

प्रश्न 3. बकरी पालन शुरू करने के लिए कितनी बकरियों की जरूरत होती है?

उत्तर- सरकार अलग-अलग यूनिट के हिसाब से योजना देती है, जैसे 10 बकरी + 2 बकरे (छोटी यूनिट), 100 बकरी + 20 बकरे (बड़ी यूनिट)

प्रश्न 4. क्या इस योजना में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा?

उत्तर- हाँ, सरकार द्वारा लाभार्थियों को बकरी पालन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पशुओं की देखभाल, पोषण, बीमारी प्रबंधन और मार्केटिंग की जानकारी शामिल होगी।

प्रश्न 5. बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने में कितना खर्च आता है?

उत्तर- खर्च यूनिट के आकार पर निर्भर करता है, लेकिन 90% सब्सिडी मिलने से किसानों को बहुत कम निवेश करना पड़ता है।

प्रश्न 6. बकरी पालन से कितनी कमाई हो सकती है?

उत्तर- अगर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए, तो किसान हर साल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूध, मांस और बकरी के बच्चों की बिक्री से आय के कई स्रोत बनते हैं।

प्रश्न 7. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर- किसान अपने नजदीकी पशुपालन विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुछ जगहों पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध होती है।

प्रश्न 8. बकरी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर- इस योजना का उद्देश्य किसानों और कमजोर वर्गों को कम लागत में स्वरोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

7000 रुपये लीटर बिकता है इस जानवर का दूध, कमाई का ऐसा तरीका जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे

एक ऐसा अनोखा पशु, जिसे लोग अब तक नजरअंदाज करते थे, लेकिन आज लाखों की कमाई का जरिया बन गया है. इसका दूध हजारों रुपये लीटर बिक रहा है और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है.

जब भी गधे का नाम आता है, तो ज्यादातर लोग उसे मेहनत और बोझ ढोने वाले जानवर के तौर पर ही देखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही गधा या खच्चर आपको लाखों की कमाई करा सकता है? अगर नहीं, तो ये खबर आपके लिए है. आज के समय में गधों और खच्चरों से कमाई के ऐसे तरीके सामने आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं.

भारत में कहाँ-कहाँ ज्यादा मिलते हैं गधे?

भारत में गधे लगभग हर राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इनकी संख्या ज्यादा है. खासकर वे इलाके जहाँ अब भी तकनीकी साधन पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं, वहाँ आज भी गधों का प्रयोग सामान ढोने और सवारी के लिए किया जाता है. इन इलाकों में गधों और खच्चरों का इस्तेमाल आज भी आम है.

गधा या खच्चर-दोनों ही कमाई के साधन

गधा और खच्चर दिखने में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही मेहनती जानवर हैं और कमाई के अच्छे साधन बन सकते हैं. खच्चर, गधे और घोड़ी के मेल से पैदा होता है, जो ताकतवर और ज्यादा सहनशील होता है. यही वजह है कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में खच्चरों का इस्तेमाल भारी सामान ढोने के लिए किया जाता है. कई लोग आज खच्चरों की खरीद-फरोख्त करके भी अच्छी कमाई कर रहे हैं. एक खच्चर की कीमत 30,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक होती है, और इसका इस्तेमाल ट्रेकिंग रास्तों, निर्माण स्थलों और पर्यटन स्थलों पर होता है.

कमाई का बेहतरीन जरिया- गधों का दूध

अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गाय या भैंस का दूध ही महंगा बिकता है, तो जरा सोचिए- गधों का दूध बाजार में 5000 रुपये से 7000 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है. इसका कारण है इसकी खासियतें. गधों के दूध में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं. आज कई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियां गधों के दूध से ब्यूटी प्रोडक्ट्स



बना रही हैं, जैसे साबुन, फेस क्रीम और लोशन. Cleopatra (क्लियोपेट्रा) के बारे में तो आपने सुना ही होगा- इतिहास में माना जाता है कि वह अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए गधों के दूध से नहाया करती थी.

इन इलाकों में सबसे ज्यादा है गधों के दूध की मांग. भारत के कई शहरी क्षेत्रों में अब गधों के दूध की डिमांड बढ़ रही है. खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां और कुछ हेल्थ स्टार्टअप इसे सीधे किसानों और पशुपालकों से खरीद रही हैं. दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में गधों के दूध का उत्पादन एक नया बिजनेस मॉडल बन चुका है. अगर आप भी इस काम में उतरना चाहते हैं, तो आपको गधियों की एक छोटी डेयरी खोलनी होगी. 10-15 गधियों के साथ शुरुआत की जा सकती है, और रोजाना 1-2 लीटर दूध से आप 5,000-10,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं.

भारत में गधों का मीट बेचना है गैरकानूनी

अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे अन्य जानवरों का

मीट बिकता है वैसे ही गधों का भी बिक सकता है, तो यह गलतफहमी अभी दूर कर लें. भारत में गधों का मीट बेचना या खरीदना पूरी तरह से गैरकानूनी है. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 429 के तहत गधों को मारना, उसका मीट बेचना या खाने पर 5 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा, सस्क्रूट (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006) के तहत भी भारत में गधों के मांस के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसलिए, यदि आप गधों या खच्चरों से कमाई

भारत के कई शहरी क्षेत्रों में अब गधों के दूध की डिमांड बढ़ रही है. खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां और कुछ हेल्थ स्टार्टअप इसे सीधे किसानों और पशुपालकों से खरीद रही हैं.

करना चाहते हैं, तो दूध, सवारी या सामान ढोने जैसे वैध और नैतिक विकल्प ही अपनाएं.

चने की कटाई के बाद खाली खेत न छोड़ें, सूरजमुखी की खेती से 90 दिन में मिल सकता है अच्छा मुनाफा!

चने की कटाई के बाद खेत खाली छोड़ने की बजाय किसान सूरजमुखी की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं. यह फसल कम पानी में तैयार हो जाती है और लगभग 90 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है. सूरजमुखी के बीजों से तेल उत्पादन होने के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है.



अक्सर किसान चने की कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं. इससे जमीन कुछ समय तक बेकार पड़ी रहती है और किसान अतिरिक्त कमाई का मौका खो देते हैं. लेकिन अगर इसी खाली खेत में सही समय पर दूसरी फसल बो दी जाए, तो वही जमीन कुछ ही महीनों में अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है. कृषि वैज्ञानिक एफ.आर. कोसरिया (उद्यान विभाग छत्तीसगढ़) के अनुसार, चने की कटाई के बाद सूरजमुखी की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला शानदार विकल्प बन सकती है.

चने के बाद सूरजमुखी की खेती क्यों फायदेमंद

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, चने की कटाई के बाद खेत में नमी और पोषक तत्व काफी हद तक मौजूद रहते हैं. ऐसे में अगर किसान उसी खेत में सूरजमुखी की बुवाई कर दें, तो उन्हें अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है. लगभग 90 से 100 दिनों में सूरजमुखी की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जिससे किसान कम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं.

खेती के लिए कैसी मिट्टी और मौसम चाहिए

कृषि वैज्ञानिक एफ.आर. कोसरिया के अनुसार, सूरजमुखी की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली

दोमट या हल्की बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. मिट्टी का पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए. इस फसल को अच्छी धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे खुले खेत में उगाना ज्यादा फायदेमंद होता है. जहां गर्मी और धूप अच्छी मिलती है, वहां सूरजमुखी की पैदावार भी बेहतर होती है. यही कारण है कि कई क्षेत्रों में किसान अब इस फसल की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.

बुवाई का सही तरीका और बीज की मात्रा

सूरजमुखी की खेती में बुवाई का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, बुवाई हमेशा कतारों में करनी चाहिए. कतार से कतार की दूरी करीब 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखना बेहतर माना जाता है. अगर एक हेक्टेयर खेत में सूरजमुखी की खेती करनी है, तो लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है. सही दूरी और सही बीज मात्रा रखने से पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और पैदावार भी अच्छी होती है.

अच्छी पैदावार के लिए खाद और सिंचाई जरूरी

अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी और खाद का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है. बुवाई से पहले खेत में 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालना

फायदेमंद माना जाता है. इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधे तेजी से बढ़ते हैं. इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश जैसे उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी जरूरी होता है. सूरजमुखी की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन समय पर सिंचाई करना जरूरी है. बुवाई के बाद अंकुरण के समय, फूल आने के समय और दाना बनने के समय सिंचाई करने से पैदावार बेहतर मिलती है.

90 दिनों में तैयार, बाजार में अच्छी मांग

सूरजमुखी की फसल लगभग 90 से 100 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाती है. अगर खेती सही तरीके से की जाए, तो एक हेक्टेयर खेत से औसतन 18 से 25 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है.

बाजार में सूरजमुखी के तेल की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए किसानों को इसका अच्छा दाम भी मिलता है. कम लागत, कम पानी और कम समय में तैयार होने वाली यह फसल किसानों के लिए आय बढ़ाने का अच्छा मौका बन सकती है. कृषि वैज्ञानिक एफ.आर. कोसरिया का कहना है कि अगर किसान चने की कटाई के बाद खेत खाली छोड़ने की बजाय सूरजमुखी की खेती करें, तो वे कम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं और अपनी खेती को ज्यादा लाभदायक बना सकते हैं.

काँफी की कीमतों में भारी गिरावट, 80 रुपये तक टूटे दाम, किसानों ने सरकार से मदद की मांग



आंध्र प्रदेश के अराकू जैसे इलाकों में स्थिति और गंभीर है. यहाँ आदिवासी किसान काँफी की खेती करते हैं, लेकिन अब सरकारी एजेंसियों ने भी खरीद बंद कर दी है. इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा.

देश में जहाँ एक तरफ अंतरराष्ट्रीय हालात का असर बड़े उद्योगों पर दिख रहा है, वहीं अब इसका सीधा असर किसानों तक पहुंच चुका है. खासकर काँफी उगाने वाले किसान इन दिनों गहरे संकट से गुजर रहे हैं. बाजार में काँफी के दाम तेजी से गिर गए हैं और हालत यह है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए खरीदार तक नहीं मिल रहे.

कीमतों में बड़ी गिरावट से बढ़ी चिंता

द ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, काँफी किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी कीमतों में आई भारी गिरावट है. पिछले साल यानी मार्च-अप्रैल 2025 में रोबस्टा चेरी काँफी की कीमत 260 से 280 रुपये प्रति किलो के बीच थी, लेकिन अब यह घटकर 180 से



205 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। यानी किसानों को सीधे 60-80 रुपये प्रति किलो तक का नुकसान हो रहा है।

इसी तरह अरेबिका कॉफी की बात करें तो इसकी कीमत भी कम हो गई है। जो अरेबिका चेरी कॉफी पिछले साल करीब 300 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, वह अब मार्च 2026 में घटकर करीब 260 रुपये प्रति किलो रह गई है। यह गिरावट किसानों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा।

वैश्विक तनाव ने बिगाड़ी सप्लाई चेन

इस पूरी समस्या की एक बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा तनाव है, खासकर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष। इसके कारण कॉफी की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है।

कॉफी किसानों का कहना है कि पहले जहां आसानी से निर्यात हो जाता था, अब वहां बड़ी दिक्कत आ रही है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और कई कंटेनर रास्ते में ही फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 300 कंटेनर भारतीय कॉफी के ऐसे हैं जो पश्चिम एशिया जाने वाले थे, लेकिन या तो बंदरगाहों पर अटके

हुए हैं या बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है।

बढ़ा खर्च, घटा व्यापार

जहां एक तरफ कीमतें गिर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्यात का खर्च बढ़ गया है। जहाजों का बीमा महंगा हो गया है, कंटेनर डिलीवरी की लागत बढ़ गई है और लंबा रास्ता तय करने के कारण माल ढुलाई का खर्च भी ज्यादा हो गया है।

कुछ यूरोपीय खरीदार अब लंबा रास्ता अपनाने लगे हैं, जैसे केप ऑफ गुड होप के जरिए शिपमेंट करना। इससे समय और लागत दोनों बढ़ रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि खरीदारों ने किसानों से खरीद कम कर दी है।

छोटे किसानों पर सबसे ज्यादा असर

भारत में ज्यादातर कॉफी किसान छोटे और सीमांत हैं। ऐसे में जब कीमतें गिरती हैं और खरीदार नहीं मिलते, तो इन किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उनकी आय सीधे घट जाती है और खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में यह संकट साफ दिखाई दे रहा है, जहां किसान अपनी फसल बेचने के

लिए परेशान हैं।

आदिवासी इलाकों में और भी मुश्किल हालात

आंध्र प्रदेश के अराकू जैसे इलाकों में स्थिति और गंभीर है। यहां आदिवासी किसान कॉफी की खेती करते हैं, लेकिन अब सरकारी एजेंसियों ने भी खरीद बंद कर दी है। इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।

सरकार से मदद की मांग

कॉफी किसानों के संगठन ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा एक निश्चित दाम मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि रोबस्टा कॉफी के लिए कम से कम 250 रुपये प्रति किलो और अरेबिका के लिए 300 रुपये प्रति किलो की गारंटी दी जाए। साथ ही सरकार और कॉफी बोर्ड को बाजार में हस्तक्षेप करके खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए।

अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो कॉफी किसानों की स्थिति और खराब हो सकती है। निर्यात में दिक्कत, बढ़ती लागत और गिरती कीमतें मिलकर इस क्षेत्र को कमजोर कर सकती हैं।



कम खर्च में दूध दोगुना करने का देसी तरीका, एक बार लगाएं यह चारा और 4 बार कटाई पाएं

डेयरी में चारे का खर्च कम करना और दूध बढ़ाना हर पशुपालक का सपना होता है। नेपियर और सूडान हरा चारा इस काम में शानदार विकल्प बन रहा है। एक बार लगाने पर 4 बार कटाई मिलती है, जिससे लागत घटती है और पशुओं को पौष्टिक आहार मिलने से दूध उत्पादन में अच्छा इजाफा होता है।

आज के समय में हर पशुपालक चाहता है कि कम खर्च में ज्यादा दूध मिले और पशु भी स्वस्थ रहें। लेकिन बाजार में मिलने वाले सप्लीमेंट, टॉनिक और दवाइयों पर खर्च बढ़ने से डेयरी का मुनाफा अक्सर घट जाता है। ऐसे में हरे चारे की एक देसी और बेहद असरदार तकनीक पशुपालकों के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है। नेपियर और सूडान जैसे पौष्टिक हरे चारे को अब कई पशुपालक हरा सोना कहने लगे हैं। वजह साफ है—एक बार इसकी खेती करने के बाद 4 बार तक कटाई की जा सकती है। इससे चारे की लागत बेहद कम हो जाती है और पशुओं को लंबे समय तक ताजा, पौष्टिक और भरपूर आहार मिलता रहता है। सबसे खास बात यह है कि इस चारे से दूध उत्पादन में शानदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे छोटे और मध्यम पशुपालकों की कमाई तेजी से बढ़ सकती है।

एक बार लगाएं, बार-बार पाएं हरा चारा

नेपियर और सूडान चारे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे एक बार लगाने के बाद बार-बार कटाई की जा सकती है। सामान्य तौर पर इसकी 4 कटाई आसानी से हो जाती है, जिससे बार-बार बीज और जुताई पर खर्च नहीं करना पड़ता। आम बोलचाल की भाषा में समझें तो यह ऐसा चारा है जो एक बार खेत में जम जाए, तो लंबे समय तक पशुओं के लिए हरा भोजन देता रहता है। छोटे किसानों के लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि कम जमीन में भी लगातार हरा चारा मिलता रहता है। इससे गर्मी और बरसात दोनों मौसम में चारे की कमी नहीं होती।

दूध उत्पादन बढ़ाने में कैसे करता है कमाल

इस हरे चारे में प्रोटीन, फाइबर और नमी अच्छी मात्रा में होती है। यही वजह है कि पशु इसे स्वाद से खाते हैं और उनका पाचन भी बेहतर रहता है। जब पशु अच्छा और संतुलित चारा खाते हैं, तो उसका सीधा असर दूध पर दिखाई देता है। कई पशुपालकों का

अनुभव है कि नियमित रूप से नेपियर और सूडान चारा खिलाने से कुछ ही महीनों में दूध उत्पादन में अच्छा उछाल देखने को मिलता है। यह चारा सिर्फ दूध ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पशुओं की कमजोरी कम करने और

तरीका है। यही वजह है कि छोटे पशुपालकों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा।

छोटे पशुपालकों के लिए क्यों है गेम चेंजर

कम जमीन और सीमित बजट वाले पशुपालकों



शरीर को मजबूत रखने में भी मदद करता है। यही कारण है कि महंगे सप्लीमेंट्स पर खर्च करने के बजाय अब कई डेयरी किसान इस प्राकृतिक विकल्प को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

कम लागत में ज्यादा मुनाफे का फॉर्मूला

डेयरी व्यवसाय में सबसे ज्यादा खर्च चारे पर होता है। अगर यही खर्च कम हो जाए तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। नेपियर और सूडान चारा इसी वजह से कम लागत वाला शानदार विकल्प माना जा रहा है। एक बार इसकी फसल तैयार होने के बाद 4 बार कटाई होने से बीज, मजदूरी और सिंचाई का खर्च काफी कम हो जाता है।

दूसरी तरफ बाजार से महंगा दाना और सप्लीमेंट खरीदने की जरूरत भी घट जाती है। यह चारा कम निवेश में ज्यादा दूध और ज्यादा मुनाफा देने वाला देसी

के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है—सालभर हरा चारा कैसे मिले। नेपियर और सूडान इस समस्या का आसान समाधान बनकर उभरा है। यह तेजी से बढ़ने वाला चारा है और एक बार खेत में अच्छी तरह जमने के बाद लगातार कटाई देता है। पशु इसे आसानी से खाते हैं, जिससे उनकी सेहत, वजन और दूध तीनों बेहतर होते हैं।

आज कई पशुपालक इसे अपनाकर डेयरी के खर्च को कम और उत्पादन को ज्यादा कर रहे हैं। यही वजह है कि यह हरा चारा अब डेयरी फार्मिंग का स्मार्ट और देसी सीक्रेट बनता जा रहा है। अगर सही तरीके से इसकी खेती और समय पर कटाई की जाए, तो यह चारा डेयरी बिजनेस को नई ऊंचाई दे सकता है। आसान शब्दों में कहें तो एक बार बोएं, 4 बार काटें और दूध के साथ कमाई भी बढ़ाएं—यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

‘फोकस स्टेट’ के रूप में बिहार ने ऊर्जा निवेश की संभावनाओं को किया रेखांकित

- ◆ ‘फोकस स्टेट’ के रूप में वैश्विक मंच पर बिहार की सशक्त उपस्थिति
- ◆ निवेशकों और उद्योग जगत के साथ सक्रिय संवाद, कई संभावनाओं पर मंथन
- ◆ बिजली क्षेत्र में 20 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव, हर घर तक पहुंची ऊर्जा
- ◆ स्मार्ट मीटरिंग और डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता व दक्षता में बड़ा सुधार
- ◆ नवीकरणीय ऊर्जा और स्टोरेज में बड़े निवेश, भविष्य के लिए स्पष्ट विजन

नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के मंच पर ‘फोकस स्टेट’ के रूप में बिहार ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य अब ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का एक उभरता हुआ और भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। यशोभूमि, नई दिल्ली में चल रहे इस वैश्विक आयोजन के दौरान बिहार ने न केवल अपनी उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, बल्कि वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ मजबूत संवाद भी स्थापित किया।

पैवेलियन से संवाद तक- निवेश की जमीन पर दिखा भरोसा

समिट में बिहार पैवेलियन लगातार चर्चा का केंद्र बना रहा। बड़ी संख्या में आगंतुकों और प्रतिनिधियों ने स्टॉल पर पहुंचकर राज्य की ऊर्जा पहलों को करीब से समझा। बीएसपीएचसीएल की कोर टीम ने मौके पर मौजूद रहकर निवेशकों और आगंतुकों के साथ विस्तृत बातचीत की और संभावित सहयोग के रास्तों को टटोला। इस दौरान कई प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बैठकें हुईं, जिनमें भविष्य की परियोजनाओं

पर गंभीर चर्चा हुई।

समिट के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में गहरी रुचि देखने को मिली। विभिन्न देशों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बिहार की नीतियों और प्रगति को करीब से समझा। इन संवादों ने यह संकेत दिया कि राज्य अब वैश्विक ऊर्जा निवेश मानचित्र पर तेजी से अपनी जगह बना रहा है और आने वाले समय में बड़े निवेश आकर्षित करने की क्षमता रखता है।

बदलाव की बुनियाद- बिजली क्षेत्र में दो दशकों की यात्रा

बिहार की इस मजबूत छवि के पीछे पिछले 20 वर्षों में हुआ व्यापक परिवर्तन है। वर्ष 2005 में जहां राज्य को 700 मेगावाट से भी कम बिजली उपलब्ध होती थी, वहीं आज 8,700 मेगावाट से अधिक की मांग पूरी की जा रही है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगभग 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है और 2.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ता नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। बिजली अब राज्य के हर गांव और घर तक पहुंच चुकी है, जिससे विकास की नई संभावनाएं खुली हैं।

इस बदलाव की नींव मजबूत अवसंरचना विकास पर टिकी है।

संचारण क्षमता में करीब 20 गुना वृद्धि, वितरण नेटवर्क का पांच गुना से अधिक विस्तार, ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या 45 से बढ़कर 175 तक पहुंचना और ट्रांसफार्मरों में दस गुना से अधिक वृद्धि—ये सभी उपलब्धियां बिहार को एक मजबूत और विश्वसनीय विद्युत नेटवर्क प्रदान करती हैं, जो औद्योगिक विकास को गति देने में सक्षम है।

राज्य की वितरण कंपनियों ने भी उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2025 में 2,000 करोड़ से अधिक के लाभ तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। AT&C हानियां घटकर राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गई हैं, और दोनों डिस्कोम्स को ‘ए’ रेटिंग मिली है, जो बेहतर कार्यकुशलता और वित्तीय अनुशासन को दर्शाती है।

डिजिटल बढ़त और भविष्य का ऊर्जा विजन

ऊर्जा सेवाओं के डिजिटलीकरण में बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाई है। 87 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे पारदर्शिता और राजस्व संग्रहण में सुधार हुआ है। साथ ही श्वक्कसिस्टम, एकीकृत आईटी डैशबोर्ड और केंद्रीकृत कमांड सेंटर जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं ने पूरे सिस्टम को अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाया है।

बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में टीबीसीबी मोड में 81000 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की योजना बनायी है। इस योजना के तहत 38950 करोड़ रुपये पावर जनरेशन की ओर लगाए जायेंगे, 16194 करोड़ ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए लगाए जायेंगे और 22951 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन तो सुदृढ़ बनाने में लगाए जायेंगे। इनके अतिरिक्त मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के मेटेनेंस और रख-रखाव के लिए 3346 करोड़ रुपये लगाए जायेंगे।

समिट के दौरान बिहार ने अपने भविष्य के ऊर्जा विजन को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। कजरा सोलर पावर प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ एकीकृत है, जो देश के सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में से एक है। पंप स्टोरेज नीति के तहत कुछ ही महीनों में 13,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलना राज्य के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 के तहत बिहार ने वर्ष 2030 तक 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 6.1 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

निवेशकों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में छूट, ऊर्जा बैंकिंग, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और कार्बन क्रेडिट जैसे प्रावधान राज्य को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहे हैं।

निष्कर्षतः भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में बिहार की यह प्रभावशाली भागीदारी केवल उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है—बिहार अब ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए निवेश, नवाचार और विकास का नया केंद्र बनने की दिशा में मजबूती से कदम रख चुका है।

इजरायल-ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट

यूपी घर बनाना हुआ 42% महंगा; सरिया, सीमेंट, मार्बल और ईंटों की कीमतें बढ़ीं

आगरा-रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अब मिडिल ईस्ट यानी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर हर भारतीय की जेब पर दिखने लगा है. युद्ध की वजह से बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है. लोहा, सीमेंट, सरिया, मार्बल, टाइल्स और सेनेटरी आइटम तक की कीमतों में 15 से 42 प्रतिशत तक का उछाल आया है. इस महंगाई ने लोगों के घर बनाने के सपनों को झटका दिया है.

मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध की वजह से आगरा में भवन निर्माण सामग्री जैसे लोहा, सीमेंट, सरिया के दाम 42% तक बढ़ गए हैं.

आगरा-रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अब मिडिल ईस्ट यानी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर हर भारतीय की जेब पर दिखने लगा है. युद्ध की वजह से बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है. लोहा, सीमेंट, सरिया, मार्बल, टाइल्स और सेनेटरी आइटम तक की कीमतों में 15 से 42 प्रतिशत तक का उछाल आया है. इस महंगाई ने लोगों के घर बनाने के सपनों को झटका दिया है.

निर्माण लागत में बढ़ोतरी- भवन निर्माण में उपयोग होने वाले लगभग सभी आइटम्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं. कारोबारियों का मानना है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं. रोटी, कपड़ा और मकान हर आम आदमी की बुनियादी जरूरत होती है. लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात ने मकान बनाना मुश्किल कर दिया है.

वैश्विक युद्ध का सीधा असर भारत पर- रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ ही अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है. जो लोग घर बनाने की योजना बना रहे थे, उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. निर्माण सामग्री की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं.

निर्माण सामग्री हुई महंगी- मकान की मजबूती के लिए लोहा, सरिया, सीमेंट, ईंट, एल्यूमीनियम और पीवीसी जैसी सामग्री जरूरी होती है. पिछले एक महीने

में इन सभी की कीमतों में तेजी आई है. इससे लोगों का बजट बिगड़ गया है. अब आम आदमी के लिए घर बनवाना मुश्किल होता जा रहा है.

लोहे और सरिया की कीमतों में उछाल- लोहा व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री दिनेश मित्तल के अनुसार वैश्विक तनाव से सबसे ज्यादा असर लोहे के कारोबार पर पड़ा है. एक महीने में लोहे के दाम करीब 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं. अफवाहों ने भी कीमतों को और बढ़ाने का काम किया है. प्रति टन कीमतों में करीब 2000 रुपये तक का अतिरिक्त दबाव देखा जा रहा है.

बाजार में मंदी और बढ़ती लागत- लोहा और सरिया कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही हैं. जबकि उपभोक्ता मांग में कमी देखी जा रही है. इसके बावजूद मटेरियल

की लागत बढ़ रही है. इसका असर खुदरा बाजार में मंदी के रूप में दिख रहा है.

सीमेंट के दाम में भी बढ़ोतरी- सीमेंट कारोबारी संतोष अग्रवाल के अनुसार एक महीने में सीमेंट के एक कट्टे पर औसतन 60 रुपये तक की वृद्धि हुई है. आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती हैं. इससे निर्माण कार्य और महंगा हो जाएगा. आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है.

ट्रांसपोर्ट लागत से बढ़ी कीमतें- आगरा में चंबल सैंड, डस्ट और ईंटों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण ढुलाई खर्च है. ट्रांसपोर्टर्स ने भाड़ा बढ़ा दिया है. डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से स्थिति और खराब हो सकती है. इससे निर्माण लागत में और इजाफा होगा.



मार्बल और पत्थर भी हुए महंगे- मार्बल कारोबारी योगेश गर्ग के अनुसार मार्बल की कीमतों में भले ही ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन दुलाई महंगी होने से प्रति फुट 5 से 8 रुपये तक की वृद्धि हुई है. पत्थर और मार्बल की दुलाई 2200 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये तक पहुंच गई है. इसका असर ग्राहकों पर पड़ रहा है.

सेनेटरी और टाइल्स सेक्टर पर असर- ऐसे ही सेनेटरी आइटम की बात करें तो एक माह में 5 से 10 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसकी वजह गुजरात के मोरबी में गैस की किल्लत के कारण सिरेमिक फैक्ट्रियों का बंद होना है. ये फैक्ट्रियां कब चालू होंगी, इसकी कोई स्पष्ट संभावना नहीं है. इससे स्टॉक का माल मनमाने दामों पर बाजार में बेचा जा रहा है.

उत्पादन लागत और कीमतों में बढ़ोतरी- टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है. आने वाले दिनों में पत्थर और मार्बल की दुलाई महंगी होने से कीमतें और बढ़ेंगी. अभी 5 रुपये तक और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. इसके कारण ग्राहकों की संख्या में करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है.

महंगे निर्माण से घटती मांग- अब केवल पैसे वाले लोग ही निर्माण कार्य करा पा रहे हैं. क्रेडिट के अध्यक्ष शोभिक गोयल के अनुसार मौजूदा हालात में भवन

निर्माण लागत 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गई है. सबसे ज्यादा असर पीवीसी फिटिंग, तार और एल्यूमीनियम उत्पादों पर पड़ा है. बीते एक महीने में पीवीसी की कीमत में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है.

एल्यूमीनियम और ऑर्डर पर असर- एल्यूमीनियम उत्पादों की कीमत में भी 25 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है. हालात ऐसे हैं कि डीलर पुराने ऑर्डर तक रद्द कर रहे हैं. लोगों की सोच में भी बदलाव आया है और वे खर्च करने से बच रहे हैं. अफवाहों ने बाजार की स्थिति को और प्रभावित किया है.

बदलती प्राथमिकताएं और बाजार की स्थिति- अब लोग जरूरी चीजों पर ही खर्च करना चाहते हैं. जान है तो जहान है जैसी सोच के कारण लोग पैसा बचा रहे हैं. सरकार का सहयोग होने के बावजूद सप्लाई बाधित है. इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट भी कीमतों को बढ़ा रही है.

ग्राहकों पर सीधा असर- आवास विकास कॉलोनी सेक्टर चार निवासी विवेक बंसल ने बताया कि उन्होंने तीन महीने पहले मकान बनवाना शुरू किया था. मकान तैयार हो चुका है और अब फिनिशिंग का काम चल रहा है. दस दिन पहले खरीदी गई टाइल्स की कीमत अब प्रति पेट्टी 80 से 85 रुपये बढ़ गई है. सेनेटरी और बिजली फिटिंग का सामान भी महंगा हो गया है.

मजबूरी में जारी निर्माण कार्य- उन्होंने बताया कि

फिनिशिंग का काम करवाना मजबूरी है, इसलिए काम जारी है. ग्राहक रिकू ने भी बताया कि उनके मकान का काम चल रहा है. ऐसे में जरूरी सामान खरीदना मजबूरी बन गया है. मौजूदा हालात में घर बनाना बेहद कठिन हो गया है.

बजट में भारी बढ़ोतरी- हर निर्माण सामग्री के दाम बढ़ चुके हैं. पहले जहां मकान बनाने का बजट 5 लाख रुपये था, अब वही बढ़कर 8 से 9 लाख रुपये तक पहुंच गया है. ऐसे में केवल वही लोग मकान बनवा पा रहे हैं जिन्होंने पहले से काम शुरू कर दिया था. नए लोग फिलहाल अपने प्लान टाल रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन पर असर- उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आगरा जोन प्रेसिडेंट देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वैश्विक तनाव के कारण पूरे विश्व में संकट के हालात हैं. अगर युद्ध लंबा चला तो हर व्यापार प्रभावित होगा. गैस की किल्लत से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिससे माल की कमी हो गई है.

व्यापारियों से अपील और चेतावनी- ट्रांसपोर्टर्स को दोनों तरफ का भाड़ा नहीं मिल रहा है. उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि आपदा को अवसर न बनाएं. कुछ लोग माल रोककर कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं. ऐसी स्थिति में सरकार और जनता का सहयोग जरूरी है ताकि देश इस संकट से मिलकर बाहर निकल सके.



BHAKTI UPASANA



APEX HOSPITAL

PRGI No.: UPHIN/2018/76675

A STATE OF THE ART MULTISPECIALITY FACILITY WITH ALL MODERN AMENITIES

E-22, NARAINA VIHAR, NEW DELHI-110 028.

Contact :-2579-3430/1552, 4553-3430, 4237-1367 Email: apex.diag@gmail.com

DR. ARVIND GUPTA, MD-MEDICINE)
9810063141

DR. USHA GUPTA, MD, PATHOLOGY
9810421552

Welcomes following Superspecialist & Specialist on its pannel

DR. PRAMOD KUMAR
(MD, DM Cardio)

DR. SANJEEV SAXENA
(MD,DM Nephro)

DR. AMAN GUPTA
(MS, MCH-Urology)

DR. RAJIV GUPTA
(DNB-ENT, MAMS)

DR. RAJIV NAYAN
(MS-SURGERY,
Laparoscopic Surgeon)

DR. GROVER
(MS-SURGERY,
Laparoscopic Surgeon)

DR. P.M. SETH
(MD-PAED)

DR. A.K. GULATI
(MD-PAED)

DR. MAHIMA
(MD-PAED)

DR. ALOKE GOEL
(MD-PAED)

DR. ANURAG SAXENA
(MD-MEDICINE)

DR. N.DUTTA
(MD-RD, Radiologist
& Ultrasonologist)

PREETI GUPTA
Dietitian
98712 90027

DR. SHASHI GUPTA
(MD-GYNAE)

DR. UMA VERMA
(MS-GYNAE)

DR. GUNJAN KACKER
(MD-DGO)

DR. ABHISHIK MEHTA
(MS-ORTHO)

DR. MANISH GUPTA
(MS-ORTHO)

DR. MANISH GOEL
(MS-ORTHO)

RMO
DR. ASHISH SHARMA (MD)

FREE OPD DAILY
(10-11 AM & 5-6 PM)

APEX + DIAGNOSTICS

OFFERS COMPLETE BODY CHECKUP

TMT • ECG • X-RAY CHEST
• ULTRASOUND
• COMPLETE BLOOD TEST
(THYROID, HBA1C) • PAP-SMEAR

